https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'वेल्थ के साथ वेल्नस चाहते हैं, तो भारत में अद्वितीय अवसर है'

वर्ष-13, अंक-03 01-15 फरवरी, 2018 (पाक्षिक) ₹20

'न्यू इंडिया' के लिए प्रतिबद्ध भाजपा

'भाजपा सरकार ने विकास के साथ-साथ सामाजिक सुधारों की भी मुहिम छेड़ी है'

'आधार' पर निराधार हैं आपत्तियां

भारत जल्द ही दुनिया का सिरमौर बनकर रहेगा

होलालकेरे (कर्नाटक) में परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

बेंगलुरू में उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक की भाजपा ईकाइयों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते श्री अमित शाह

वाराणसी, उत्तर प्रदेश में एक विशाल 'युवा उद्घोष' रैली को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

वाराणसी में 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वैलरी' के उद्घाटन अवसर पर उप्र के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और अन्य के साथ श्री अमित शाह

वाराणसी में 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वैलरी' की स्मारिका जारी करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, साथ में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री महेंद्र नाथ पांडेय, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ व अन्य

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार की उलटी गिनती शुरू हो गई है: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 10 जनवरी को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिला स्थित होलालकेरे में 79 दिनों तक चलने वाली कर्नाटक के नवनिर्माण की परिवर्तन यात्रा को संबोधित किया और कर्नाटक...

वैचारिकी

हमें पुरुषार्थ करना होगा 14

श्रद्धांजलि

पं. दीनदयाल उपाध्यायः कुशल संगठक व विचारक राजनेता 16

लेख

'आधार' पर निराधार हैं आपत्तियां 18
भारत जल्द ही दुनिया का सिरमौर बनकर रहेगा 23
वामपंथी दुनिया में भारत को कलंकित करने का कुत्सित प्रयास कर... 24
पीएम मोदी ने भारत की विदेश नीति में आमूलचूल बदलाव कर... 30

अन्य

प्रत्यक्ष करों के संग्रह में 18.7 प्रतिशत का इजाफा 11
प्रधानमंत्री द्वारा 43 हजार करोड़ रुपए की राजस्थान रिफाइनरी कार्य का... 15
कर चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में 184 प्रतिशत की वृद्धि 17
भारत-इजराइल के बीच साइबर सहयोग समेत 9 अहम समझौते 20
'वेल्थ के साथ वेल्नस चाहते हैं, तो भारत में अद्वितीय अवसर है' 26
डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी : एक शिक्षाविद् 32

स्थायी स्तंभ

सोशल मीडिया से 04
पत्र-पत्रिकाओं से 33
स्फुट विचार 33

संगठनात्मक गतिविधियां

08 'भाजपा सरकार ने विकास के साथ-साथ सामाजिक सुधारों की भी मुहिम छेड़ी है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष...

सरकार की उपलब्धियां

12 पर्यटन से हुई 1,80,379 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा आमदनी

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 17 जनवरी को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 के दौरान...

13 पीएसएलवी ने लांच किया एक साथ 31 सैटेलाइट

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के ध्रुवीय सेटेलाइट लांच व्हीकल ने 12 जनवरी...

29 जीएसटी परिषद की 25वीं बैठक में कई प्रमुख नीतिगत बदलाव

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 18 जनवरी को नई दिल्ली में जीएसटी...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

हमें हमारी सेना और सैनिकों पर गर्व है। OROP को 40 वर्षों की मांग के बाद अगर किसी सरकार ने लागू किया, तो वो हमारी सरकार है। OROP के नाम पर कांग्रेस ने देश और सेना को गुमराह किया।

@AmitShah

क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा व उनके सम्मान के लिए जीवन भर कार्य किए। महिला विरोधी कुरीतियों को ध्वस्त कर महिलाओं के सम्मान की जो परिभाषा उन्होंने रची है, वह सदियों तक हम सभी को प्रेरित करती रहेगी।

@JPNadda

भारत सरकार विशेष पहलों के जरिए गरीबों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार के प्रति प्रतिबद्ध है, खास तौर पर उन राज्यों में जो बीमारियों से निपटने में अपेक्षाकृत कम संसाधित हैं। एनएचपी 2017 ने पूरे देश में स्वास्थ्य में सुधार हेतु निगरानी के लिए 'डिजीज बर्डेन ट्रेकिंग' की अनुशंसा की है।

facebook

नए साल के पहले दिन राजनांदगांव में श्रमिक भाई-बहनों के साथ भोजन का आनंद लिया। उन्हें पांच रुपए में ताज़ा व पौष्टिक भोजन मिले, इसलिए सरकार ने 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना' की शुरुआत की है।

— डॉ. रमन सिंह

महात्मा गांधी जी ने कहा था असली भारत गांव में बसता है, हमारी सरकार गांवों के विकास के लिए कई अहम योजनाएं चला रही है। कृषि और किसानों का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा संताल परगना में 3 हजार कि.मी. सड़कों का निर्माण कराया गया है।

— रघुबर दास

लालू प्रसाद को एक-एक कर चारा घोटाले के तीन मामलों में सजा सुनाए जाने के बाद पहले न्यायपालिका को जातिवादी बताने की कोशिश की गई, फिर भाजपा पर साजिश रचने का निराधार आरोप लगाया गया और अब राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए अपराधियों की पीठ पर हाथ रखकर हिंसात्मक घटनाओं को हवा दी जा रही है। विपक्ष के पास गरीबों-पिछड़ों के उत्थान का कोई कार्यक्रम नहीं रह गया है।

— सुशील कुमार मोदी

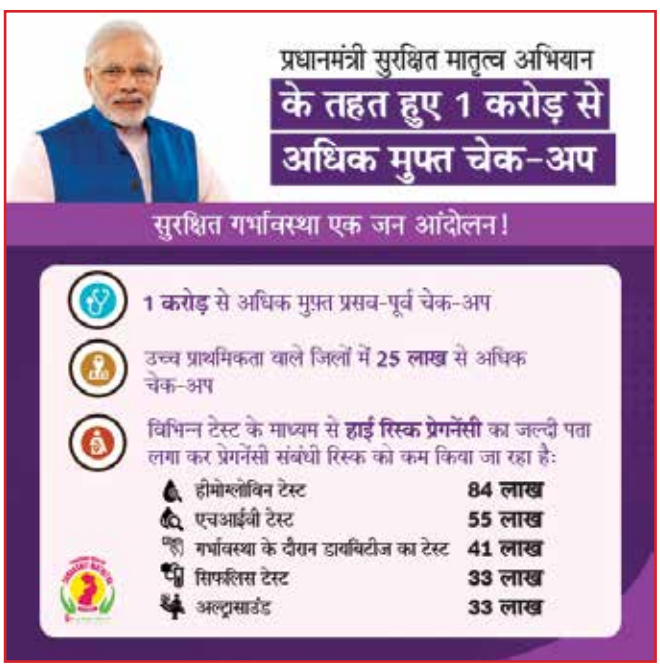

सहयोग और सामंजस्य जरूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम' के अपने संबोधन में जब 'वसुधैव कुटुंबकम' की प्राचीन अवधारणा की व्याख्या की, तब दावोस में भारत का यह मंत्र 'समस्त विश्व एक परिवार है' गूंज उठा। प्रधानमंत्री ने अपने सारगर्भित संबोधन में इस वर्ष के विषय 'क्रिएटिंग ए शेयर्ड फ्यूचर इन ए फ्रेक्चर्ड वर्ल्ड' पर बोलते हुए स्थानीय से वैश्विक तक अनेक विषयों को छुआ। जब पूरा विश्व पूरी तन्मयता से विश्व को बेहतर बनाने हेतु भारत की चिंताओं एवं प्राथमिकताओं को सुन रहा था, प्रधानमंत्री के शब्द सभी के मन में गहरी छाप छोड़ रहे थे। भारत द्वारा प्राचीनकाल से ही शांति, सौहार्द और बंधुता के लिए दिखाए राह की चर्चा जब प्रधानमंत्री कर रहे थे, दरारों, बंटवारों एवं विवादों के दलदल से बाहर एक सांझा भविष्य की प्रस्तावना वे रख रहे थे। यह वास्तव में हर भारतीय के लिये एक गौरव का क्षण था।

प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद एवं सिकुड़ता वैश्वीकरण को ठीक ही विश्व समुदाय के समक्ष बड़ी चुनौतियों के तौर पर गिनाया। भारतीय परंपरा जिसमें पृथ्वी को 'मां' कहा जाता है, की ओर इंगित करते हुए उन्होंने इशोपनिषद् से भगवान बुद्ध के 'अपरिग्रह' तथा महात्मा गांधी की आवश्यकता अनुरूप दोहन, न कि लोभ आधारित आकांक्षाओं को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का उपाय बताया। उन्होंने यह भी बताया कि भारत किस प्रकार से इस क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री विश्व के हर मंच पर आतंकवाद के विषय को निरंतर मजबूती से उठाते रहे हैं। उन्हें हर वैश्विक मंच पर आतंकवाद को एजेंडे पर प्रमुखता से लाने में सफलता भी मिली। दावोस में भी उन्होंने इस खतरे की ओर सबका ध्यान खींचा और 'अच्छा आतंकवाद' और 'बुरा आतंकवाद' के बीच खींची गई काल्पनिक रेखा के खतरे पर जोर दिया। उन्होंने वैश्वीकरण की गति को बाधित कर रहे 'प्रोटेक्शनिज्म' की नीतियां जिससे देशों के बीच नई 'टैरिफ' की दीवारें खड़ी की जा रही है, पर चिंता व्यक्त की। कुछ देशों के आत्म–केन्द्रित नीतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य का रास्ता वैश्वीकरण की ओर जाता है न कि अलग–थलग होने में। असल में वैश्विक व्यवस्था बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय स्तर पर मेलजोल, सहयोग एवं सामंजस्य स्थापित करने में है, जो विविधता में तालमेल बिठाने के सिद्धांतों पर आधारित है। विश्व समुदाय को इन चुनौतियों का सामना करने को तैयार होना पड़ेगा।

सरकार जहां 'लाइसेंस–परमिट' को समाप्त कर रही है, रेड–टेप' का स्थान अब 'रेड कार्पेट' ने ले लिया है और निवेशकों के लिए नए अवसर अब उपलब्ध हैं, वहां अब बड़े परिवर्तन हो रहे हैं तथा तकनीक के माध्यम से उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता सुनिश्चित किया जा रहा है। 'डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डायनेमिज्म एवं डेवलपमेंट' से देश की 'डेस्टिनी' लिखी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि हर प्रकार की दरारों को लोकतंत्र तथा विविधता के प्रति सम्मान, सौहार्द, परस्पर सहयोग, एवं संवाद से पाटा जा सकता है, जिससे विश्व शांति, स्थिरता एवं विकास सुनिश्चित हो सकता है।

भारत आज पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण है, जहां विविधता पुष्पित–पल्लवित हुई है और लोकतंत्र दिनोंदिन मजबूत हो रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने ठीक ही कहा कि लोकतंत्र एवं विविधता; भारत की जीवनधारा है तथा शांति, सौहार्द एवं संकल्प से विविधता में लोकतंत्र एक जोड़ने वाली शक्ति बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और समावेशी विकास उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है जिसका मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास' है, जो समावेशी 'विजन' एवं 'मिशन' के साथ कार्य कर रही है। भारत आज 'रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांस्फॉर्म' पर विश्वास करता है, जिसका प्रभाव इसकी नीतियों में परिलक्षित है तथा परिणाम यह है कि मात्र साढ़े तीन वर्ष में देश में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सरकार जहां 'लाइसेंस–परमिट' को समाप्त कर रही है, रेड–टेप' का स्थान अब 'रेड कार्पेट' ने ले लिया है और निवेशकों के लिए नए अवसर अब उपलब्ध हैं, वहां अब बड़े परिवर्तन हो रहे हैं तथा तकनीक के माध्यम से उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता सुनिश्चित किया जा रहा है। 'डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डायनेमिज्म एवं डेवलपमेंट' से देश की 'डेस्टिनी' लिखी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि हर प्रकार की दरारों को लोकतंत्र तथा विविधता के प्रति सम्मान, सौहार्द, परस्पर सहयोग, एवं संवाद से पाटा जा सकता है, जिससे विश्व शांति, स्थिरता एवं विकास सुनिश्चित हो सकता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि हर प्रकार की विविधता एवं दरारों के बीच भारत हमेशा सौहार्द एवं समन्वय स्थापित करने की अपनी भूमिका निभाता रहेगा। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार की उलटी गिनती शुरू हो गई है: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 10 जनवरी को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिला स्थित होलालकेरे में 79 दिनों तक चलने वाली कर्नाटक के नवनिर्माण की परिवर्तन यात्रा को संबोधित किया और कर्नाटक की बदहाली के लिये कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पर जमकर प्रहार किया। ज्ञात हो कि कर्नाटक में परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं भाजपा के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी श्री बी. एस. येदुरप्पा के नेतृत्व में पिछले वर्ष 02 नवंबर को शुरू हुई थी जो राज्य के 224 विधान सभाओं की गांव-गलियों से गुजरते हुए 28 जनवरी, 2018 को पूर्ण होगी और इसका समापन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 02 नवंबर, 2017 को बेंगलुरु में परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया था। अभी तक परिवर्तन यात्रा 69 दिनों में 174 विधान सभाओं तक पहुंची है और इसने 8,000 किलोमीटर की दूरी तय की है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक परिवर्तन यात्रा के दौरान हमने प्रदेश के युवाओं में जो जोश देखा है, राज्य की जनता में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के प्रति जो गुस्सा और आक्रोश देखा है, इससे यह स्पष्ट है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार की उलटी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने जनता के विकास से सिद्धारमैया सरकार का कनेक्शन काट दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारें आम जनता की भलाई के लिये होती हैं, लेकिन कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार केवल कांग्रेसियों के भले के लिए ही चल रही है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इन साढ़े तीन सालों में कर्नाटक के विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, लेकिन कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार इन योजनाओं को जनता तक पहुंचने ही नहीं देती। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार कर्नाटक की मदद नहीं कर रही, आज मैं इसका जवाब देने आया हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 13वें वित्त आयोग में सेन्ट्रल शेयर के रूप में कर्नाटक को केवल 88,583 करोड़ रुपये दिये थे, जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने कर्नाटक को 2,19,506 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है जो कांग्रेस की यूपीए सरकार की तुलना में ढाई गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त मुद्रा योजना में 39 हजार करोड़, स्मार्ट सिटी में 960 करोड़, अमृत मिशन के लिए 4900 करोड़, बेंगलुरु मेट्रो के लिए 2617 करोड़, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 204 करोड़ रुपये, बसों की खरीद के लिए 239 करोड़ रुपये, स्वायल हेल्थ कार्ड के लिए 31 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 600 करोड़ रुपये, रेलवे के विकास के लिए 2197 करोड़ रुपये और सड़कों के निर्माण के लिए लिए लगभग 27,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। लेकिन ये पैसा कर्नाटक की जनता तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि भ्रष्टाचारी सिद्धारमैया सरकार केवल राजनीति करना चाहती है, विकास नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी

सरकार ने कर्नाटक को इन क्षेत्रों में लगभग 79 हजार करोड़ रुपये दिए हैं, इस तरह मोदी सरकार ने कर्नाटक को विकास के लिए लगभग तीन लाख करोड़ रुपये की राशि दी है। उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि आप मेरा क्या हिसाब मांगते हैं, कर्नाटक की जनता दो लाख करोड़ रुपये का हिसाब आपसे मांग रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कर्नाटक में 3.33 लाख करोड़ गरीब माताओं को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा कर्नाटक के विकास के लिए दिया गया पैसा कर्नाटक के कांग्रेसी नेताओं के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अनुदान राशि के साथ-साथ कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार राज्य की जनता का भी अरबों-खरबों रुपये खा गई है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड को तोड़ कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि क्या किसी आम जनता को कभी 70 लाख रुपये की घड़ी भेंट में मिली है, लेकिन इस तरह की भेंट कर्नाटक के मुख्यमंत्री को क्यों मिलती है, ऐसा इसलिए है कि यहां के मुख्यमंत्री जनता के पैसे को उद्योगपतियों पर लुटाते हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अर्कावती लेआउट की 50 एकड़ जमीन के लैंड यूजेज को बदल दिया, तीन साल से इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा कि कांग्रेसी गरीबों की दाल-चावल भी खा जाते हैं, मंत्री के पत्नी लाखों रुपये लेते हुए स्टिंग में पकड़ी जाती हैं। अवैध खनन के कारण कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के एक मंत्री को 6 महीने में ही इस्तीफा देना पड़ता है। लाइब्रेरी में सेलरी बढ़ाने के लिए तीन करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी जाती है, सिटी स्कैन/एमआरआई के लगाने का कॉन्ट्रैक्ट सरकार में बैठे नेताओं के रिश्तेदारों को दिया जाता है। अपने परिवार वालों को 150 करोड़ रुपये की पीडीए की जमीन अवैध तरीके से हस्तांतरित कर दिया जाता है, इसके आधुनिकीकरण में 900 करोड़ रुपये का घोटाला होता है, इस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटक को बदहाल करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार के मंत्री डीके शिवकुमार के घर रेड पड़ती है, करोड़ों रुपये का कच्चा चिट्ठा पकड़ा जाता है, लेकिन आज भी वे मंत्रिमंडल में बने हुये हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्यों ये लोग अब तक मंत्रिमंडल में बने हुए हैं? उन्होंने कहा कि कर्नाटक में स्टील ब्रिज की मंजूरी के लिए 100 करोड़ रुपये की किस्मत मांगी जाती है, 300 मेगावाट सोलर पावर में भी रिश्वत मांगी जाती है और गोविंदराज की डायरी खोलें तो भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा ही सामने आ जाता है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार ने राज्य के मछुआरों-किसानों की चिंता किये बगैर ही कर्नाटक के लगभग 1800 से अधिक तालाबों को डिमोडिफाइड कर दिया, आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है?

श्री शाह ने कर्नाटक में भाजपा एवं विचार परिवार के कार्यकर्ताओं पर हो रहे हिंसक हमलों पर कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले चार साल में कर्नाटक में 20 से अधिक संघ परिवार एवं भाजपा के बेकसूर कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गई है। क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी के पास इसका कोई जवाब है? उन्होंने कहा कि क्यों सिद्धारमैया सरकार इन मामलों की सही जांच नहीं कर रही? उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से भाजपा एवं संघ कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाने के लिए एक्शन लेने को कहा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की आयु लंबी नहीं है, राज्य में भाजपा की सरकार आते ही दोषियों को सजा दी जायेगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इस सरकार को राज्य एवं देश की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है और इसलिए इसने वोट बैंक की राजनीति की खातिर देश विरोधी कार्यों में संलिप्त SDPI के ऊपर से सारे केस हटा लिए हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दिए जाने की मांग 1955 से लगातार हो रही थी, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का विधेयक लेकर संसद में आई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राज्य सभा में पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का हितैषी होने की बातें करते हैं, लेकिन ओबीसी कमीशन को

संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाले विधेयक को राज्य सभा में गिराने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है।

श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक में सैकड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। चित्रदुर्ग जिले में पिछले तीन साल से अकाल है, लेकिन सिद्धारमैया सरकार के माथे पर जूं तक नहीं रेंगती। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार से राज्य के युवा खुश नहीं हैं, किसान खुश नहीं हैं, महिलायें खुश नहीं हैं, यह सरकार एक पल के लिए भी सत्ता में बने रहने का हक़ खो चुकी है। अब इस सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि मैं कर्नाटक की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से विनती करने आया हूं कि आप राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक ऐसी मजबूत सरकार का गठन करें जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य का विकास करे और इसे एक अग्रणी राज्य के रूप में विकसित करे। उन्होंने सभा के माध्यम से कर्नाटक की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि आप आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कर्नाटक में श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर कर्नाटक को कांग्रेस-मुक्त बनाएं। ■

'भाजपा सरकार ने विकास के साथ-साथ सामाजिक सुधारों की भी मुहिम छेड़ी है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 20 जनवरी को वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्पोर्ट्स ग्राउंड में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 'युवा उद्घोष' कार्यक्रम को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' की नीति पर श्री योगी आदित्यनाथ सरकार में उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम की भूरि-भूरि प्रशंसा की। 'युवा उद्घोष' के इस कार्यक्रम में वाराणसी लोकसभा के 1,736 बूथों के प्रत्येक बूथ से 10 युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इन सभी कार्यकर्ताओं ने डिजिटल भुगतान करके पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पूरे हिंदुस्तान की ऊर्जा का अक्षय स्रोत और आध्यात्मिक केंद्र है। उन्होंने कहा कि सोने पर सुहागा है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी, बाबा संकटमोचन की नगरी और दादा भैरव की नगरी वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं। उन्होंने 'युवा उद्घोष' कार्यक्रम में भाजपा के साथ जुड़ने के लिए युवाओं का हृदय से पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल होने के साथ-साथ एक विचारधारा, एक आंदोलन और प्रधानमंत्री श्री

भारतीय जनता पार्टी में मेरी शुरुआत भी एक बूथ अध्यक्ष के रूप में हुई थी। देश में भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो एक बूथ कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचने का मौक़ा देती है, जो किसी चाय बेचने वाले गरीब के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनने का मौक़ा देती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वाराणसी के भौतिक विकास (सड़क, बिजली, पानी, इन्फ्रा) के लिए जो किया है, वह यदि कांग्रेस शासन में पिछले 70 सालों में हुआ होता तो आज वाराणसी अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर चुका होता।

नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के पुनर्निर्माण का संकल्प भी है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने गुलामी के जमाने में भारत का जयघोष विश्व संसद में किया और आजादी के 70 साल बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पूरे विश्व में भारत का जयघोष कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं का भाजपा में स्वागत करते हुए कहा कि जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं, तब आप विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सदस्य बनते हैं, आप एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं जिसके 330 से अधिक सांसद, 1397 से अधिक विधायक हैं, देश के 19 राज्यों में जिसकी सरकारें हैं और जो पार्टी देश के 80% भू-भाग पर जनता की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थापना के समय से लेकर आज तक हमारी परंपरा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जाति अथवा धर्म के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि यह विचारधारा और कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में मेरी शुरुआत भी एक बूथ अध्यक्ष के रूप में हुई थी। उन्होंने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो एक बूथ कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचने का मौक़ा देती है, जो किसी चाय बेचने वाले गरीब के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनने का मौक़ा देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वाराणसी के भौतिक विकास (सड़क, बिजली, पानी, इन्फ्रा) के लिए जो किया है, वह यदि कांग्रेस शासन में पिछले 70 सालों में हुआ होता तो आज वाराणसी अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर चुका होता। उन्होंने कहा कि महज 3 साल के अंदर वाराणसी में 2900 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिये गये हैं और आज विकास धरातल पर दिखाई भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आज 'युवा उद्घोष' कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी लोगों से एक बात फिर से कहना चाहता हूं कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के आध्यात्मिक गौरव को एक इंच भी कम किये बगैर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम यहां की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य निरंतर जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे पुरातन नगरी का संदेश समग्र विश्व में गौरव के साथ जाना चाहिए कि किस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गाथा भारत में चल रही है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साढ़े तीन साल में देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, युवा एवं महिलाओं के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम शुरू किये हैं और इसे नीचे तक पहुंचाने का प्रबंध किया है। उन्होंने कहा कि देश के गरीबों की चिंता पहली बार यदि किसी सरकार ने की है तो वह मोदी सरकार है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में लगभग साढ़े तीन करोड़ गरीब महिलाओं को गैस का कनेक्शन देकर धुएं से मुक्ति दिलाई गई है। आजादी के 70 साल बाद बिजली से वंचित लगभग 19 हजार गांवों के इलेक्ट्रीफिकेशन की योजना शुरू की गई है जिसे मई, 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। साढ़े 9 करोड़ से अधिक

युवाओं को मुद्रा बैंक योजना के तहत स्वरोजगार प्रदान किया गया है और लगभग साढ़े सात करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वाराणसी के साथ-साथ देश भर के कई शहरों को अर्बन डेवलपमेंट मिशन के तहत स्मार्ट सिटी बनाने की नई पहल की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना का संपुट तैयार किया गया है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विकास के साथ-साथ सामाजिक सुधारों की भी मुहिम छेड़ी है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने हुए 23 सप्ताह का अवकाश देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और अदालत ने सरकार से पूछा कि इस विषय पर सरकार का स्टैंड है तो मोदी सरकार ने वोट बैंक की परवाह किये बगैर यह स्पष्ट कर दिया कि इस देश में ट्रिपल तलाक नहीं चल सकते। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक के बदले में सजा का प्रावधान करके जब हम संसद में क़ानून लेकर आये तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया, लेकिन अब कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति नहीं चलने वाली।

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की प्रशंसा करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। एक साल से भी कम समय में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि यूपी में किसानों के फसल की सरकार द्वारा रिकॉर्ड खरीदी हुई है और उनका पैसा सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार आने के बाद से अपराध में यूपी का ग्राफ धीरे-धीरे नीचे की ओर जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य की क़ानून-व्यवस्था सुदृढ़ न हो, उस राज्य के युवाओं का भविष्य अंधकारमय होता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विकास के साथ-साथ सामाजिक सुधारों की भी मुहिम छेड़ी है। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने हुए 23 सप्ताह का अवकाश देने की व्यवस्था की गई है। हमारी मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरु हुई और अदालत ने सरकार से पूछा कि इस विषय पर सरकार का स्टैंड है तो मोदी सरकार ने वोट बैंक की परवाह किये बगैर यह स्पष्ट कर दिया कि इस देश में ट्रिपल तलाक नहीं चल सकते।

उन्होंने कहा कि इतने अल्प समय में सीमित संसाधन के बावजूद योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की क़ानून-व्यवस्था को सुधारने का काम किया है, मैं इसके लिए उनको बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि योगी जी के आने के बाद से गांव हो या शहर, 15 से 24 घंटे बिजली देने का काम उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, दोनों मिलकर यूपी और भारत को आगे ले जाने का काम कर रहे है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश की मदद करने के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी और जो मदद मिलती है। उसको पारदर्शी तरीके से नीचे तक पहुंचाने में योगी सरकार भी अथक परिश्रम कर रही है, इसके कारण आज यूपी विकास के रास्ते पर तेज गति से अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि जब हम फिर से विधान सभा चुनाव में जायेंगे, उस वक्त उत्तर प्रदेश देश के सबसे विकसित राज्यों में शुमार होगा। उन्होंने कहा कि योगी श्री आदित्यनाथ के नेतृत्व में टॉप पर जाने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी यूपी के सांसद भी हैं, इसका फायदा यूपी को बहुत मिल रहा है। उन्होंने युवाओं का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि आप सब 1950 से आज तक निरंतर चल रही एक महान परंपरा से जुड़ रहे हैं। साथ ही, आप प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा और भारत के पुनर्निर्माण यात्रा के साथ भी जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी यात्रा भारत के विकास की यात्रा के साथ हमेशा जुड़ी रहे, यही मेरी शुभकामना है। ■

प्रत्यक्ष करों के संग्रह में 18.7 प्रतिशत का इजाफा

15 जनवरी तक 6.89 लाख करोड़ रुपये का कर संग्रह

प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आंकड़ों से पता चला है कि 15 जनवरी, 2018 तक 6.89 लाख करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में हुए शुद्ध संग्रह की तुलना में 18.7 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि के दौरान प्रत्यक्ष करों का यह शुद्ध संग्रह वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रत्यक्ष करों के कुल बजट अनुमानों (9.8 लाख करोड़ रुपये) का 70.3 प्रतिशत है। अप्रैल 2017 से लेकर 15 जनवरी, 2018 तक की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह (रिफंड के लिए समायोजन से पहले) 13.5 प्रतिशत बढ़कर 8.11 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। अप्रैल 2017 से लेकर 15 जनवरी, 2018 तक की अवधि के दौरान 1.22 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए हैं।

चालू वित्त वर्ष के दौरान सभी पैमानों पर प्रत्यक्ष करों के संग्रह में निरंतर उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रत्यक्ष करों के कुल संग्रह की वृद्धि दर पहली तिमाही के 10 प्रतिशत से बढ़कर दूसरी तिमाही में 10.3 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 12.6 प्रतिशत और 15 जनवरी, 2018 तक की अवधि में 13.5 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह प्रत्यक्ष करों के कुल शुद्ध संग्रह की वृद्धि दर भी पहली तिमाही के 14.8 प्रतिशत से बढ़कर दूसरी तिमाही में 15.8 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 18.2 प्रतिशत और 15 जनवरी, 2018 तक की अवधि में 18.7 प्रतिशत हो गई है।

प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत विशेषकर कॉरपोरेट आयकर (सीआईटी) के संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सीआईटी का सकल संग्रह पहली तिमाही में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाने के बाद इससे भी ज्यादा बढ़कर दूसरी तिमाही में 5.1 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 10.1 प्रतिशत और 15 जनवरी, 2018 तक की अवधि में 11.4 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह सीआईटी के शुद्ध संग्रह की वृद्धि दर भी दूसरी तिमाही के 10.8 प्रतिशत से बढ़कर तीसरी तिमाही में 17.4 प्रतिशत और 15 जनवरी, 2018 तक की अवधि में 18.2 प्रतिशत हो गई है। ■

अब केंद्र सरकार वित्त वर्ष के अंत में 30,000 करोड़ रुपये कम उधार लेगी

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने राजस्व प्राप्तियों और व्यय के रुझान से यह आकलन किया है कि सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए केवल 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी ही वित्तीय जरूरतों की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगी। गौरतलब है कि सरकार ने कुछ दिन पहले कहा था कि वह चालू वित्त वर्ष 2017-18 में दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए बाजार से 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी जुटाएगी। इस प्रकार अब केंद्र सरकार वित्त वर्ष के अंत में 30,000 करोड़ रुपये कम उधार लेगी।

दरअसल, सरकार ने पिछली तीन नीलामियों में 15,000 करोड़ रुपये की उधारियों को स्वीकार नहीं किया। शेष 15,000 करोड़ रुपये की राशि को आगामी हफ्तों के अधिसूचित उधारी कार्यक्रम से कम कर दिया जाएगा।

दूध उत्पादन की वृद्धि दर उच्च स्तर पर बरकरार

पिछले तीन वर्षों के दौरान दूध उत्पादन की वृद्धि दर उच्च स्तर पर बरकरार रही है। गौरतलब है कि वर्ष 2016-17 के दौरान देश में दूध उत्पादन में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 20.13 प्रतिशत की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। यही नहीं, वर्ष 2016-17 के दौरान दूध उत्पादन में वर्ष 2015-16 के मुकाबले 6.4 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है। दूध उत्पादन की वृद्धि दर वर्ष 2014-15 में 6.3 प्रतिशत, वर्ष 2015-16 में 6.3 प्रतिशत और वर्ष 2016-17 में 6.4 प्रतिशत रही है। इस प्रगतिशील तस्वीर को ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष (2017-18) में भी डेयरी क्षेत्र धीरे-धीरे तेज रफ्तार पकड़ते हुए डेयरी विकास से जुड़ी राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुमानित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो गया है।

जहां तक सीजनल अनुमान का सवाल है, कुल दूध उत्पादन वर्ष 2016-17 (ग्रीष्म) के 51.33 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2017-18 (ग्रीष्म) में 53.77 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच गया है, जो 4.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है। यह वृद्धि दर वर्ष 2015-16 के मुकाबले वर्ष 2016-17 के दौरान दूध उत्पादन में दर्ज की गई 3.9 प्रतिशत के मुकाबले अधिक है। अतः यहां तक कि वर्ष 2017-18 के ग्रीष्म सीजन के दौरान भी दूध उत्पादन की वृद्धि दर निरंतर उच्च स्तर पर विराजमान रही है। वर्ष 2017-18 के ग्रीष्म सीजन के दौरान प्रथम पांच सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। ■

पर्यटन से हुई 1,80,379 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा आमदनी

केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 17 जनवरी को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 के दौरान विदेशी मुद्रा आमदनी (एफईई) वर्ष 2016 की तुलना में 17.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,80,379 करोड़ रुपये हो गई, जबकि वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में यह 14.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,54,146 करोड़ रुपये दर्ज की गई थी। दूसरे शब्दों में, अमेरिकी डॉलर के लिहाज से दिसंबर, 2017 के दौरान एफईई 3.038 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई, जबकि यह दिसंबर 2016 में 2.439 अरब अमेरिकी डॉलर और दिसंबर 2015 में 2.126 अरब अमेरिकी डॉलर दर्ज की गई थी।

गौरतलब है कि पर्यटन मंत्रालय रुपये एवं डॉलर दोनों ही लिहाज से भारत में हर महीने पर्यटन के जरिए विदेशी मुद्रा आमदनी (एफईई) का आकलन करता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान संतुलन से जुड़े यात्रा प्रमुख के क्रेडिट डेटा पर आधारित होता है।

दिसंबर 2017 और जनवरी-दिसंबर, 2017 के दौरान भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आमदनी (एफईई) के अनुमानों की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं –

दिसंबर, 2017 में एफईई 19,514 करोड़ रुपये रही, जबकि दिसंबर, 2016 में यह 16,558 करोड़ रुपये और दिसंबर, 2015 में 14,152 करोड़ रुपये थी। दिसंबर, 2016 के मुकाबले दिसंबर, 2017 में रुपये के लिहाज से एफईई की वृद्धि दर 17.9 प्रतिशत दर्ज

की गई, जबकि दिसंबर, 2015 के मुकाबले दिसंबर, 2016 में यह वृद्धि 17.0 प्रतिशत आंकी गई थी।

दिसंबर 2016 के मुकाबले दिसंबर 2017 में अमेरिकी डॉलर के लिहाज से एफईई की वृद्धि दर 24.6 प्रतिशत रही, जबकि दिसंबर 2015 की तुलना में दिसंबर 2016 में यह वृद्धि दर 14.7 प्रतिशत रही थी। वर्ष 2017 के दौरान एफईई वर्ष 2016 की तुलना में 20.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 27.693 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई, जबकि वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में यह 8.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 22.923 अरब अमेरिकी डॉलर दर्ज की गई थी। ■

हज यात्रियों के लिए सब्सिडी खत्म

हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को इस साल से कोई रियायत नहीं मिलेगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 16 जनवरी को घोषणा की कि हज यात्रा पर दी जाने वाली रियायत इस साल से खत्म हो गई है। दरअसल, यह फैसला तुष्टीकरण के बगैर अल्पसंख्यकों को सशक्त करने के अजेंडे का एक हिस्सा है। गौरतलब है कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में हज सब्सिडी को धीर-धीरे 2022 तक खत्म करने को कहा था।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज सब्सिडी के फंड को मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सब्सिडी का फायदा एजेंट्स उठा रहे थे, इसलिए हज सब्सिडी बंद कर दी गई है। गरीब मुस्लिमों के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी।

खास बात यह है कि भारत से करीब 1300 महिलाएं इस बार बिना महरम (परिवार का वह पुरुष जिससे शादी संभव नहीं) के हज यात्रा करेंगी। रियाद ने इस मामले में अपने नियमों में थोड़ी ढील देते हुए 45 साल से अधिक उम्र की कम से कम 4 महिलाओं के समूह को बिना किसी साथी के यात्रा की अनुमति दे दी है।

गौरतलब है कि सरकार इस फैसले से हज यात्रा करानेवाले कॉन्ट्रैक्टरों की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाना चाहती है। सच तो यह है कि 2018 में अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा यात्री हज यात्रा पर जाने वाले हैं। दरअसल, हाल ही में सऊदी अरब ने भारतीय यात्रियों के लिए कोटा 5 हजार और बढ़ा दिया है। अब कुल 1.75 लाख भारतीय नागरिक हज की यात्रा पर जा सकते हैं। ■

पीएसएलवी ने लांच किया एक साथ 31 सैटेलाइट

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के ध्रुवीय सेटेलाइट लांच व्हीकल ने 12 जनवरी अपने 42वें उड़ान में सफलतापूर्वक 710 किलोग्राम का कार्टोसैट-2 श्रृंखला का दूर-संवेदी उपग्रह 30 सहयात्री उपग्रहों के साथ श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लांच किया। इसे पीएसएलवी-सी 40 नाम दिया गया है।

पीएसएलवी-सी 40 को भारतीय समयानुसार सवेरे 9 बजकर 29 मिनट पर प्रथम लांच पैड से छोड़ा गया। 16 मिनट 37 सेकेंड के उड़ान के बाद उपग्रह ने विषुवत रेखा से 97.55 डिग्री के कोण पर झुके 503 किलोमीटर के पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट को हासिल कर लिया। आगे के 7 मिनटों में केट्रोसेट-2 श्रृंखला का उपग्रह आईएनएस-आईसी तथा 28 कस्टमर उपग्रह पूर्व निर्धारित क्रम में पीएसएलवी से सफलतापूर्वक अलग हो गए। पीएसएलवी-सी40 के

चौथे चरण को संक्षिप्त समय के लिए दो बार छोड़ा गया, ताकि 300 किलोमीटर ऊंचाई के पोलर ऑर्बिट को हासिल किया जा सके। इसमें भारत का माइक्रोसेट सफलतापूर्वक अलग हो सके।

अलग-अलग होने के बाद कार्टोसैट-2 श्रृंखला की दो सौर श्रृंखलाएं स्वतः तैनात हो गई और इसरो के बंगलुरू स्थित टेलिमेट्री, ट्रैकिंग, कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) ने उपग्रह का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। आने वाले दिनों में उपग्रह के संचालन को अंतिम रूप देने के लिए लाया जाएगा। इसके बाद यह अपने पैंक्रोमेटिक (श्याम और श्वेत) तथा मल्टीस्पेक्ट्रल (रंगीन) कैमरों का इस्तेमाल करते हुए दूरसंवेदी डाटा प्रदान करना शुरू करेगा।

कार्टोसेट-2 के दो भारतीय सहयात्री उपग्रहों 11 किलोग्राम के आईएनएस-आईसी तथा 100 किलोग्राम का माइक्रोसैट की निगरानी और नियंत्रण बंगलुरू के आईएसटीआरएसी से किया जा रहा है। भारत के अलावा इनमें 28 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह हैं, जो कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, कोरिया गणराज्य, ब्रिटेन तथा अमेरिका के हैं। गौरतलब है कि पीएसएलवी ने अब तक विदेश से सफलतापूर्वक 11 भारतीय उपग्रह तथा 237 कस्टमर उपग्रह लांच किया है। ■

प्रधानमंत्री ने इसरो की टीम को अपने 100वें उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की टीम को अपने 100वें उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, "आज पीएसएलवी के सफल प्रक्षेपण पर इसरो और उसके वैज्ञानिकों की मैं हृदय से प्रशंसा करता हूं। नए साल में यह सफलता हमारे नागरिकों, किसानों, मछुआरों आदि को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की तेजी से बढ़ोतरी का लाभ पहुंचाएगी।

उन्होंने कहा कि इसरो द्वारा 100 वीं उपग्रह का शुभारंभ अपनी शानदार उपलब्धियों और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के उज्ज्वल भविष्य को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत की सफलता के लाभ हमारे भागीदारों के लिए भी उपलब्ध हैं। आज प्रक्षेपित किए गए 31 उपग्रहों में से 28, छह अन्य देशों से संबंधित थे।"

अग्नि-5 बैलेस्टिक मिसाइल की सफल पांचवीं परीक्षण उड़ान

जमीन से जमीन पर मार करने वाली लंबी दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का 18 जनवरी को सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण उड़ान 9 बजकर 53 मिनट पर ओड़िशा के डॉ. अब्दुल कलाम आईलैंड से की गयी। मिसाइल का यह पांचवां परीक्षण था। सभी पांचों अभियान सफल रहे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एएसएल, डीआरडीएल, आईटीआर, आरसीआई और टीबीआरएल प्रयोगशालाओं के निदेशकों ने संपूर्ण लांच ऑप्रेशन की समीक्षा की। इस अवसर पर सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। डीआरडीओ के अध्यक्ष एवं डीडीआर एण्ड डी के सचिव डॉ. एस क्रिस्टोफर ने अग्नि-5 टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अग्नि-5 की लगातार पांचवीं सफल परिक्षण उड़ान से देश की रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी।

रक्षामंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में रक्षा उद्योग विकास समागम का उद्घाटन करते हुए अग्नि-5 की सफल परीक्षण उड़ान पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इस सफलता के लिए डीआरडीओ को बधाई दी। उन्होंने मिसाइल के निर्माण में घरेलू प्रोद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए भारतीय उद्योगों की प्रशंसा की। ■

हमें पुरुषार्थ करना होगा

| दीनदयाल उपाध्याय |

गतांक का शेष

पश्चिम ने राज्य के हाथ में ही सब कुछ दे दिया। बाकी संगठन राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं। पोप और खलीफाओं ने राज्य को काबू में कर लिया या राज्य ने बाकी पर कब्जा कर लिया। इंग्लैंड के चर्च ने राज्य पर कब्जा किया। रूस ने श्रमिकों के द्वारा राज्य पर कब्जा किया। इसका कारण था, वहां केवल राज्य संस्था थी। हमने कहा, सब संगठित हों तो चारों में कोई विरोध नहीं होगा। व्यवस्था का अर्थ संगठित जीवन होता है। हमारे यहां तभी वर्ण व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। जहां यह व्यवस्था नहीं, उसे मलेच्छ देश या राज्य कहा। ऐसी जगह रहना ठीक नहीं समझा गया। हम वर्ग बनाते हैं। अलग-अलग व्यवस्था करते हैं। वर्ग तो हुए किंतु भेद कहां है? आपस में ऊंच-नीच का विशेष स्थान नहीं है। सब समाज के अंग हैं। विभाग तो चाहिए वर्ग चलाने के लिए। समाज को भी पांच संस्थाएं होती हैं। शक्तियों का विभक्तीकरण करना पड़ता है। समाज में गड़बड़ आई तो एक वर्ग बन जाता, अपना काम छोड़, बाकी की बातों पर विचार करना शुरू कर देता है।

जब ये वर्ग एक-दूसरे पर कब्जा करना चाहते हैं, तो वहीं गड़बड़ हो जाती है। जातियां बन जाती हैं। जैसे एक जाति कबीरपंथी बन गई। जब एक संस्था बाकी के बीच में दखल दे तो समस्या पैदा होती है। व्यापारी राज्य पर क़ब्जा करना चाहे, राज्य शिक्षा पर, तो इस दखल (Interference) को वर्ण-संकरता कहते हैं। राज्य ने अपना काम छोड़ दिया। सरकार पुलिस, सेना, डाकू आदि का खयाल छोड़कर भिलाई का कारखाना, जीवन बीमा आदि पर ध्यान देने लगती है। परिणामतः व्यवस्था बिगड़ती है। भ्रष्टाचार बढ़ता है। यह वर्ण-व्यवस्था

राष्ट्र की आत्मा यह संस्कृति है। इसके लिए एक शास्त्रीय शब्द है 'चिति'। यह चिति ही समाज की विशेषता है। इसकी रक्षा के लिए सभी प्रयत्नशील रहते हैं। बाकी सबकुछ छोड़कर भी इसे लेने को सब तैयार रहते हैं। चिति हमारे लिए परम सुख है। हमारे यहां धर्म की भावना, निष्ठा को 'चिति' रूप में स्वीकार किया गया है।

कर्तव्य, गुणों के आधार पर चलने वाली वैज्ञानिक व्यवस्था है। यह प्रतिबंधक नहीं, जन्म से या कर्म से सुविधानुसार होता है। जितने साधन चलते हैं, वे तत्त्व के बलबूते पर। तत्व समाज में आत्मीयता,

स्वत्व लाता है। जैसे कुटुंब के अंदर ज्ञान होता है, लेकिन जब वह ज्ञान क्षीण हो जाता है तब अव्यवस्था पैदा होती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो सभी कुछ खत्म हो जाता है।

राष्ट्र की आत्मा यह संस्कृति है। इसके लिए एक शास्त्रीय शब्द है 'चिति'। यह चिति ही समाज की विशेषता है। इसकी रक्षा के लिए सभी प्रयत्नशील रहते हैं। बाकी सबकुछ छोड़कर भी इसे लेने को सब तैयार रहते हैं। चिति हमारे लिए परम सुख है। हमारे यहां धर्म की भावना, निष्ठा को 'चिति' रूप में स्वीकार किया गया है। मोक्ष को परम पुरुषार्थ इसीलिए कहा गया है। धर्म के नाम पर कितने ही लोगों को बलिदान देना पड़ा। छोटे-से-छोटे व्यक्ति ने भी बलिदान दिया। यह स्वभाव हमारे अंदर पैदा होते ही माता के दूध द्वारा आता है। यह हकीकत है। गुरु गोविंद सिंहजीं के बच्चे बलिदान हो गए थे, लेकिन उनके अंदर इतनी दृढता कहां से आई, इतना कोई शायद करोड़ प्रशंसा कमाकर भी न कर पाए। हमारा मस्तक गौरव से ऊंचा हो जाता है, बलिदानी लोगों की कथा जब हम सुनते हैं। यदि रोटी ही सबकुछ होती तो लोग आज धर्म के नाम पर घर आदि क्यों छोड़ देते हैं। आर्थिक समस्या ही सबकुछ होती तो ऐसा नहीं होता। उनके अंतर में भी चिति का भाव छुपा हुआ होता है। क्या ईरान में सब मुसलमान बन गए? कुछ पारसी अपवादस्वरूप जैसे हमारे यहां अपवादस्वरूप मुसलमान बने।

राष्ट्र जीवन का केंद्र धर्म नहीं कहा, 'चिति' के आधार पर समाज की संगठित शक्ति होती है, जिसे विराट् कहा। इसके जाग्रत होने पर ही फिर समाज टिकता है। फिर सब व्यवस्था ठीक चलती है। समष्टि, भूत शक्ति यह विराट् Joint Stock Company लुटेरों का नहीं, अपितु चिति एव धर्म के आधार पर संगठन होता है। यह शरीर में प्राण की तरह रहती है, जिसके कारण इंद्रियां काम करती हैं। इंद्रियों का यदि आपस में झगड़ा हो जाए तो सबकुछ गड़बडा जाता है। एक बार शरीर की सब इंद्रियों में आंख, कान, हाथ, पैर में आपस में झगड़ा हो गया। सभी एक-दूसरे से अपने को बड़ा बताने लगे। उनका झगड़ा

खत्म नहीं हो रहा था, तो सारे मिलकर ब्रह्माजी के पास गए। ब्रह्माजी ने उन्हें सुझाया कि स्वयं सारे आपस में निर्णय कर लो। जिसके न करने से सब कुछ बेकार हो जाए वही सबसे बड़ा है। सारे खुशी-खुशी लौट आए। सबसे पहले आंखो ने सोचा कि हमें छुट्टी पर जाना चाहिए तब इनको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। आंखें चली गईं। लेकिन शरीर ने टटोल-टटोलकर काम चला लिया। किसी ने रास्ता दिखा दिया। आंखों ने वापस आकर हालचाल पूछा। लेकिन वहां तो सबकुछ ठीक-ठाक है। अबकी बार कानों ने सोचा कि अब हमें छुट्टी करके देखना चाहिए, लेकिन कानों के बिना भी इशारे से काम चल गया। अब हाथों का नंबर था। हाथ चले गए, लेकिन हाथों और पैरों के बिना भी सरक-सरक कर काम चल गया। अब प्राणों की बारी आई, प्राणों ने सोचा कि सभी ने आजमाकर देख लिया है। अब मैं भी आजमाकर देख लूं। लेकिन जैसे ही प्राण जाने लगे, सभी कुछ ठंडा होने लगा। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। हाथ-पैर सुन्न हो गए। यहां तक कि बुद्धि ने भी सोचना बंद कर दिया। सभी ने प्राणों से प्रार्थना की कि वे न जाएं। अब हमें पता चल गया है कि प्राण ही सबसे बड़े हैं।

यानी हमारी चिति हमारे राष्ट्र का प्राण है। प्राण यदि कमज़ोर हो जाए तो सभी इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं। प्राणों को बलवान करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने बाह्य के रूप के स्थान पर तत्त्व का विचार किया। किसी ने कहा कि दूध अच्छा, किसी ने दूध फटा हुआ पीया था, उसने कहा कि दूध तो खराब होता है। जैसा अनुभव हुआ, उसने वैसी ही परिभाषा दी। एक मंडल बनाया गया जाति-पांति का भेदभाव मिटाने के लिए, लेकिन जाति-पांति तोड़क मंडल के नाम से एक अलग ही जाति बन गई। पेड़ के पत्ते सूख रहे हैं, झड़ रहे हैं। उनके झड़ने से काम नहीं चलेगा। उनकी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो व्यवस्था लाभदायक नहीं है, चिति के अनुकूल नहीं है, वह भी अपने आप समाप्त हो जाएगी। राष्ट्र के प्राणों को जगाने का काम करना पड़ेगा। शक्ति का जागरण करना होगा। राष्ट्र की साधना का हमारा काम धर्म के आधार पर ही होता है। ■ ...समाप्त

- जून 14, 1958

प्रधानमंत्री द्वारा 43 हजार करोड़ रुपए की राजस्थान रिफाइनरी कार्य का शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 जनवरी को राजस्थान के बाड़मेर स्थित पचपदरा में राजस्थान रिफाइनरी के कार्य का शुभारंभ होने के अवसर पर एक विशाल सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे और केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही दिन पहले भारत में मकर संक्रान्ति बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। उन्होंने कहा कि यह त्योहारी सीजन समृद्धि का अग्रदूत है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न तरह के त्योहारों के तत्काल बाद वह एक ऐसी परियोजना के लिए राजस्थान आकर अत्यंत प्रसन्न हैं, जो अनगिनत लोगों के जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएगी।

दरअसल, राजस्थान के पास प्रचुर मात्रा में तेल और गैस का भंडार है। राजस्थान रिफाइनरी राज्य की पहली रिफाइनरी होगी। इसका निर्माण 9 एमएमटीपीए के रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर के रूप में किया गया है। इस रिफाइनरी के उत्पाद भारत स्टेज-6 उत्सर्जन मानको के अनुरूप होंगे। परियोजना की अनुमानित लागत 43 हजार करोड़ रुपऐ है और यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह 'संकल्प से सिद्धि' का समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने लक्ष्यों की पहचान करनी है और देश की आजादी के 75वें साल यानी वर्ष 2022 तक उनकी प्राप्ति के लिए अथक कार्य करने हैं। प्रधानमंत्री ने पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत के योगदान का स्मरण किया और कहा कि उन्होंने राजस्थान के आधुनिकीकरण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया था। उन्होंने वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री जसवंत सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश में श्री जसवंत सिंह ने उल्लेखनीय योगदान दिया है।

प्रधानमंत्री ने सूखे के हालात का समुचित प्रबंधन करने और कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए आम जनता की भरपूर मदद करने हेतु राज्य सरकार और मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की भूरि-भूरि प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार सशस्त्र बलों के लिए 'वन रैंक, वन पेंशन' को एक वास्तविकता बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने इसे संभव बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं।

प्रधानमंत्री ने 'जन धन योजना' का उल्लेख किया और कहा कि गरीबों की पहुंच अब बैंकिंग सेवाओं तक सुनिश्चित हो गई है। उन्होंने रसोई गैस से जुड़ी 'उज्ज्वला योजना' के साथ-साथ 18,000 गैर विद्युतीकृत गांवों में बिजली पहुंचाने की दिशा में हुई उल्लेखनीय प्रगति का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के हितों और प्रगति के प्रति मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की कटिबद्धता के लिए उनकी सराहना की। ■

पं. दीनदयाल उपाध्यायः :
कुशल संगठक व विचारक राजनेता

(25 सितम्बर 1916–11 फ़रवरी 1968)

स्वतंत्र भारत की राजनीति में कुछ ही महापुरुष ऐसे हुए हैं, जो 'विचार और कर्म' दोनों के धनी हों। पं. दीनदयाल उपाध्याय ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो कुशल संगठक तो थे ही, साथ ही मौलिक विचारक भी थे। उन्होंने 16 वर्षों तक देशभर में प्रवास करके भारतीय जनसंघ को एक मजबूत संगठन बनाया और 'एकात्ममानव दर्शन' जैसी विचारधारा का प्रतिपादन कर भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय वैचारिक अधिष्ठान भी प्रस्तुत किया।

दीनदयालजी 'सादा जीवन–उच्च विचार' के पुजारी थे। उनकी वेशभूषा सामान्य थी, लेकिन उनके विचार बड़े प्रेरक और प्रखर थे। खद्दर का कुर्ता, धोती, साधारण कैनवास के रबड़ के सोल वाले जूते, मोटा चश्मा, एक सामान्य झोला, जिसमें कुछ किताबें और एक जोड़ी पहनने के कपड़े। आम आदमी की तरह उनकी वेशभूषा थी।

25 सितम्बर 1916 को जन्मे दीनदयालजी ने बचपन से ही विकट परिस्थितियों का सामना किया। ढाई वर्ष की अवस्था में उनके पिताजी का देहांत हो गया। सात वर्ष के थे तो माताजी का निधन। जब वे नवीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब छोटा भाई शिवदयाल का देहांत। 1935 में नानी चल बसी। 1940 में ममेरी बहन का निधन। मृत्यु ने उन पर निरंतर आघात किए, लेकिन उन्होंने इन परिस्थितियों का मन मजबूत कर सामना किया।

दीनदयालजी पढ़ने में बहुत तेज थे। मामा राधारमण, जो गंगापुर में सहायक स्टेशन मास्टर थे, के पास रहकर प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई की। दसवीं की परीक्षा कल्याण हाईस्कूल सीकर से दी। वे न केवल प्रथम श्रेणी से उतीर्ण हुए वरन् समस्त बोर्ड की परीक्षा में वे सर्वप्रथम रहे। 1937 में इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में बैठे और न केवल समस्त बोर्ड में सर्वप्रथम रहे, वरन् सब विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त की। 1939 में सनातन धर्म कॉलेज, कानपुर में प्रथम श्रेणी में बीए उत्तीर्ण किया। आगरा में एमए (अंग्रेजी) प्रथम वर्ष में उन्हें प्रथम श्रेणी के अंक मिले। 1941 में 25 की उम्र में बीटी करने प्रयाग गए।

दीनदयालजी 1937 में बीए की पढ़ाई के लिए कानपुर गए, तब अपने सहपाठी बालूजी महाशब्दे के माध्यम से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्पर्क में आए, वहीं उनकी भेंट संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार से हुई। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जब कानपुर आए, तो उन्होंने उनको शाखा आमंत्रित कर बौद्धिक वर्ग करवाया। अपनी पढ़ाई पूर्ण करने तथा संघ का द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रचारक बन गए और आजीवन प्रचारक रहे। वे संघ में 1937 से 1951 तक रहे। दीनदयालजी सन् 1952 में जनसंघ के अखिल भारतीय महामंत्री बने और 16 वर्ष तक इस दायित्व को संभाला। 1968 में वे भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने।

दीनदयालजी स्वाध्यायी प्रवृत्ति थे। जब भी समय मिलता लिखते–पढ़ते रहते थे। दीनदयालजी सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे। उन्होंने भारतीय राजनीति में मूल्यों का परिष्कार किया। दीनदयालजी गांव–गांव तक प्रचार करते थे। ज्यादातर रेलगाड़ी में सफर करते थे। ऐसा इसलिए कि एक तो उन्हें पढ़ने–लिखने का समय मिलता था और स्टेशनों पर कार्यकर्ताओं से भेंट हो जाती थी। दीनदयालजी की कुशल संगठन क्षमता से प्रभावित होकर भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने कहा था, ''यदि मुझे दीनदयालजी जैसे चार–पांच लोग मिल जाएं, तो मैं पूरे देश में जनसंघ को खड़ा कर लूंगा।"

दीनदयालजी का कहना था कि हमारी संस्कृति और परंपरा में दुनिया को देने योग्य क्या-क्या बातें हैं, उन्हें जानें और विश्व की प्रगति में अपना सहयोग दें। लंबे अरसे तक हमारा सारा ध्यान स्वाधीनता संग्राम व आत्मरक्षा में लगा रहा। अतः हम दुनिया के अन्य राष्ट्रों की बराबरी में खड़े नहीं हो सके हैं, पर आज जब हम स्वतंत्र हैं, तो हमें इस कमी को पूरा करना होगा।

11 फरवरी 1968 के मनहूस दिन को दीनदयालजी हमसे विदा हो गए। उनका शव मुगलसराय में पाया गया। संसद में प्रायः किसी ऐसे व्यक्ति के लिए शोक प्रस्ताव पारित नहीं होता, जिसका संसद से कोई नाता ना रहे। दीनदयालजी जी ऐसे गिने चुने उन लोगों में रहे, जिनके प्रति संसद में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ■

3547 करोड़ रुपये में 72,400 असाल्ट राइफलों एवं 93,895 कार्बाइनों की खरीद की मंजूरी

रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की 16 जनवरी को हुई बैठक में 'मेक II' प्रक्रिया, जो भारतीय उद्योग जगत के जरिये रक्षा उपकरण के विकास एवं विनिर्माण के लिए अनुसरण किए जाने वाले दिशानिर्देशों को निर्धारित करती है, को सरल बनाया गया। डीएसी ने सीमाओं पर तैनात टुकड़ियों की तात्कालिक आवश्कता की पूर्ति हेतु रक्षा बलों को सक्षम बनाने के लिए 3547 करोड़ रुपये में त्वरित आधार पर 72,400 असाल्ट राइफलों एवं 93,895 कार्बाइनों की खरीद की मंजूरी दी।

रक्षा डिजाइन एवं उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने एवं 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए परिषद ने आज रक्षा खरीद प्रक्रिया के 'मेक II' वर्ग में उल्लेखनीय बदलाव लागू किया। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि 'मेक II' परियोजना में कोई भी सरकारी वित्त पोषण शामिल नहीं है, डीएसी ने न्यूनतम सरकारी नियंत्रण के साथ इसे उद्योग के अनुकूल बनाने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया। संशोधित प्रक्रिया के प्रमुख पहलू अब रक्षा मंत्रालय को अब स्वयं प्रेरित प्रस्तावों को स्वीकार करने में समर्थ बनाएंगे तथा स्टार्टअप कंपनियों को भी भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उपकरण विकसित करने की अनुमति प्रदान करेंगे। 'मेक II' परियोजनाओं में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड में भी क्रेडिट रेटिंग तथा वित्तीय नेटवर्थ मानदंड में कमी लाने से संबंधित शर्तों को हटाने के द्वारा छूट दी गई है।

पहले की 'मेक II' प्रक्रिया के अनुसार, प्रोटोटाइप उपकरणों के विकास के लिए केवल दो वेंडरों का चयन किया गया था। अब आर्हता के छूट प्राप्त मानदंडों को पूरा करने वाले सभी वेंडरों को प्रोटोटाइप विकास प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। वेंडरों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। परिषद द्वारा 'मेक II' परियोजना की मंजूरी प्राप्त होने के बाद सेवा मुख्यालय (एसएचक्यू) स्तर पर सभी मंजूरियां प्रदान की जाएंगी।

उद्योग एवं स्टार्टअप कंपनियों को आरंभिक स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए एसएचक्यू डिजाइन एवं विकास चरण के दौरान एसएचक्यू एवं उद्योग के बीच प्राथमिक संयोजक के रूप में कार्य करने के लिए परियोजना सुगमीकरण टीमों का गठन करेगा। ये टीमें वेंडर की आवश्यकता के अनुरूप तकनीकी इनपुट, परीक्षण अवसंरचना तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करेंगी। अगर कोई एकल व्यक्ति या कंपनी भी कोई नया समाधान प्रस्तुत करती है तो अब एसएचक्यू के पास वेंडर की विकास पहल को स्वीकार करने तथा प्रसंस्करण का विकल्प होगा। एसएचक्यू को पहुंच बढ़ाने तथा उद्योग के बीच जागरुकता फैलाने के लिए निजी क्षेत्र से इस क्षेत्र के विशेषज्ञों/ सलाहकारों की सेवाएं लेने की अनुमति होगी।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सफल वेंडर के पास एश्योर्ड ऑर्डर हैं, केवल वेंडर द्वारा डिफॉल्ट किए जाने के मामले को छोड़कर, परियोजना के मंजूर हो जाने के बाद इसे पुरोबंध नहीं किया जाएगा। ■

कर चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में 184 प्रतिशत की वृद्धि

आयकर विभाग काले धन की समस्या से निपटने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विभाग ने कर चोरी के कई मामलों में कानून कार्रवाई शुरू की है। विभिन्न अपराधों के लिए कानूनी कार्रवाई की पहल की गई है, जिनमें जान बूझकर कर चोरी करना अथवा किसी प्रकार के कर का भुगतान नहीं करना; जान बूझकर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करना; सत्यापन में फर्जी जानकारी और स्रोत पर काटे गए/ संग्रहित कर को जमा नहीं करना अथवा इसमें अत्यधिक देरी करना शामिल है।

वित्त वर्ष 2017-18 (नवम्बर 2017 को समाप्त अवधि तक) के दौरान विभाग ने 2225 मामलों में विभिन्न अपराधों के लिए कानूनी कार्रवाई करने संबंधी शिकायतें दाखिल की, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 784 शिकायतें दाखिल की गई थीं, जो 184 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। वर्तमान वित्त वर्ष (नवम्बर 2017 को समाप्त अवधि तक) के दौरान विभाग द्वारा संयोजित शिकायतों की संख्या 1052 थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 575 थी। मामलों में 83 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अपराधों का संयोजन तब किया जाता है जब बकायेदार अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और निर्धारित शर्तों के अनुसार संयोजित शुल्क दे देता है।

कर चोरों के खिलाफ विभाग द्वारा निर्णायक और केन्द्रित कार्रवाई करने के कारण अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए चूककर्ताओं की संख्या में वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान तेजी से वृद्धि दर्ज की गई। वर्तमान वर्ष (नवम्बर 2017 को समाप्त अवधि तक) के दौरान विभिन्न अपराधों के लिए 48 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया, जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या 13 थी, इनकी संख्या में 269 प्रतिशत वृद्धि हुई। ■

'आधार' पर निराधार हैं आपत्तियां

रविशंकर प्रसाद

देश की विकास यात्रा में आधार क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। यह बिचौलियों व भ्रष्टाचार को खत्म कर गरीबों तक उनका हक पहुंचा रहा है। डिजिटल समावेशन व डिजिटल सशक्तीकरण डिजिटल इंडिया के दो प्रमुख लक्ष्य हैं, जिन्हें हासिल करने में आधार अहम भूमिका निभा रहा है। यह सुरक्षित होने के साथ-साथ डिजिटल इंडिया के परिवर्तनकारी व समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक किफायती और सशक्त माध्यम भी है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में आज 119 करोड़ लोग आधार के तहत पंजीकृत हो चुके हैं और लगभग 99 प्रतिशत जनसंख्या के पास आधार उपलब्ध है। कल तक भ्रष्टाचार और शासकीय संवेदनहीनता से जूझ रहे मनरेगा मजदूर के चेहरे पर आज इसलिए मुस्कान है, क्योंकि आधार के कारण उसकी कड़ी मेहनत का मेहनताना सीधे उसके बैंक खाते में पहुंच रहा है। आधार के कारण ही लगभग 80 हजार फर्जी शिक्षकों को निकालना संभव हुआ। आधार जनता के पैसे बचा रहा है। फर्जी गैस कनेक्शन, फर्जी राशन कार्ड या फर्जी शिक्षकों को हटाकर लगभग 57 हजार करोड़ रुपए की जो बचत हुई है, उसका लाभ गरीबों के लिए चल रही योजनाओं को ही होगा।

संप्रग सरकार और राजग सरकार के आधार में बड़ा फर्क है। संप्रग सरकार के समय आधार को कोई कानूनी, विधायी सुरक्षा या मान्यता हासिल नहीं थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने आधार को तकनीकी रूप से मजबूत और सुरक्षित बनाने के अलावा एक सबल कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की है। आधार कानून न केवल आधार के उपयुक्त रखरखाव को सुनिश्चित करता है, बल्कि उसकी पूरी प्रणाली को एक उत्तरदायी प्रशासन भी बनाता है। इसमें भी सबसे अहम है व्यक्ति की निजता की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधानों की व्यवस्था। यह कानून आधार बायोमेट्रिक डाटा के दुरुपयोग के लिए कड़े दंड और आपराधिक अभियोग का प्रावधान भी करता है। कोर बायोमेट्रिक जैसे कि उंगलियों के निशान और आंखों के स्कैन पूरी तरह से एन्क्रिप्ट रूप में रखे जाते हैं, जिसे तोड़ पाना लगभग असंभव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आधार सत्यापन की प्रक्रिया में आधार सर्वर को भी यह ज्ञात नहीं होता कि सत्यापन किस मकसद के लिए किया जा रहा है। आधार द्वारा रोज करीब छह करोड़ से अधिक सत्यापन किए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आधार बस इतना बताता है कि जिस अधिकृत संस्था ने आपके आधार नंबर पर जिन उंगलियों के निशान या आंखों के निशान का सत्यापन मांगा है, वे आधार के डाटाबेस में रखी जानकारी से मेल खाते हैं या नहीं? यदि जानकारी सही पाई जाती है तो आधार इसे सत्यापित करता है और अगर गलत पाई जाती है तो रद्द कर देता है। आप जिन सेवाओं के लिए आधार का प्रयोग करते हैं, उनसे संबंधित आपकी व्यक्तिगत जानकारियां आधार अपने डाटाबेस में जमा नहीं करता। आधार के पास आपकी जाति, धर्म, शैक्षणिक योग्यता व स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां नहीं होतीं। लिहाजा यह कहना पूरी तरह निराधार है कि आधार आपकी निजी सूचनाओं की प्रोफाइल बना रहा है।

नरेंद्र मोदी सरकार ने आधार को तकनीकी रूप से मजबूत और सुरक्षित बनाने के अलावा एक सबल कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की है। आधार कानून न केवल आधार के उपयुक्त रखरखाव को सुनिश्चित करता है, बल्कि उसकी पूरी प्रणाली को एक उत्तरदायी प्रशासन भी बनाता है। इसमें भी सबसे अहम है व्यक्ति की निजता की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधानों की व्यवस्था।

आधार एक डिजिटल पहचान है, जो आपकी भौतिक पहचान को और पुख्ता करता है। आधार के कानून के तहत आपके बायोमेट्रिक डाटा को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अपरिहार्य परिस्थितियों में ही जाहिर किया जा सकता है। वह भी तब जब भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी इसका लिखित कारण बताते हुए सरकार से इसका अनुरोध करे। यह अनुरोध भी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली उस

समिति द्वारा अनुशंसित हो, जिसमें विधि सचिव और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव भी शामिल हों। इस परिस्थिति में भी आपके बायोमेट्रिक डाटा को एक सीमित समय के लिए ही उपलब्ध कराया जा सकता है।

आधार के माध्यम से 76 करोड़ बैंक खातों का सत्यापन किया जा चुका है। इससे न केवल खाताधारकों की डिजिटल पहचान की जा सकती है, बल्कि आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए बैंक खातों के दुरुपयोग पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। इससे आम नागरिकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन काले धन के कारोबारियों, आतंक को पोषित करने और अपराधियों को संरक्षण देने वालों को जरूर चिंतित होना पड़ेगा।

किसी न किसी प्रकार की डिजिटल पहचान आज दुनिया में बेहद आम हो गई है। फिर चाहे वह ड्राइविंग लाइसेंस हो या मतदाता पहचान पत्र हो, उनकी जानकारी संबंधित विभागों की वेबसाइटों पर नियमित रूप से उपलब्ध होती है। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट या किसी निजी कंपनी में प्रवेश के लिए भी आप डिजिटल पहचान के बाद ही दाखिल हो पाते हैं। कई देशों में वीजा जारी करने के लिए उंगलियों के निशान मांगे जाते हैं। आजकल कई अच्छे स्मार्टफोन भी आपकी उंगलियों या चेहरे की पहचान से ही खुलते हैं। इन सभी गतिविधियों में डिजिटल पहचान देने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन आधार के बारे में बहुत आपत्तियां हैं। आधार कानून के तहत किसी भी गरीब को किसी सरकारी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। सरकारें गरीब व्यक्ति को उसके पास उपलब्ध पहचान पत्र का प्रयोग कर सरकारी योजनाओं का लाभ दें और साथ ही यह प्रयास भी करें कि उसका आधार भी बनवाया जा सके।

निजता के मामले में अधिक स्पष्टता की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने निजता के मामलों का मौलिक ढांचा तैयार कर दिया है और जाहिर तौर पर इसे संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़कर देखा है। निजता की आड़ में तकनीकी क्षेत्र में हो रही नई खोजों को रोका नहीं जा सकता। नई खोज करने के लिए डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। देश आज डाटा अन्वेषण का एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है जो सूचना-प्रौद्योगिकी से जुड़ी खोजों, अर्थव्यवस्था के विकास और रोजगार सृजन के लिए एक सुनहरा अवसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में डाटा के प्रयोग से नई खोजों की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए निजता का तर्क भ्रष्ट और अपराधियों के बचाव की ढाल नहीं बन सकता। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जो एक सक्षम डाटा सुरक्षा कानून के संबंध में अपनी सिफारिशें जल्द ही देगी।

पूरी व्यवस्था बायोमेट्रिक डाटा की सुरक्षा के पैमानों पर खरी उतरती है और यह विशेषज्ञों की सतत निगरानी में रहती है। जो लोग अपना आधार नंबर साझा नहीं करना चाहते, उनकी सुविधा के लिए हाल में वर्चुअल आईडी की व्यवस्था भी शुरू की गई है। आधार की सफलता जगजाहिर है। विश्व बैंक ने 2016 में जारी विश्व विकास रिपोर्ट में कहा, 'भारत के आधार जैसा डिजिटल पहचान तंत्र किसी भी सरकार को समावेशी विकास करने में मददगार होता है। आधार ने भारत की डिजिटल उपलब्धियों को नया आधार दिया है। ■

(नई दुनिया से साभार)

लेखक केंद्रीय संचार एवं प्रौद्योगिकी और विधि व न्याय मंत्री हैं

विश्व की बोवाईन आबादी का 18 प्रतिशत भारत में: राधा मोहन सिंह

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि भारत में 30 करोड़ बोवाईन है, जो विश्व की बोवाईन आबादी का 18 प्रतिशत हैं। पारंपरिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से सैकड़ों वर्षों की मेहनत के बाद देश के देशी बोवाईन आनुवंशिक संसाधन विकसित हुए हैं और आज हमारे पास गोपशुओं की 42 नस्लों के साथ-साथ याक और मिथुन के अलावा भैंसों की 13 नस्लें हैं। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने यह बात 17 जनवरी को नई दिल्ली में पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा सामूहिक भ्रूण अंतरण संबंधी काफी टेबल पुस्तक के विमोचन के मौके पर कही।

श्री राधा मोहन सिंह ने 20वें लाइव स्टॉक सेंसस के लिए डाटा इकट्ठा करने के लिए सॉफ्टवेयर भी लांच किया। श्री सिंह ने कहा कि 20वें लाइव स्टॉक सेंसस में प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया इनेशियेटिव के हिस्से के रूप में टेबलेट कम्प्यूटर का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। सॉफ्टवेयर में सभी प्रकार के एनालिटिकल रिपोर्ट्स तैयार करने और सेंसस ऑपरेशन के रियल टाइम निगरानी की भी व्यवस्था होगी।

श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने अगले पांच वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में डेयरी क्षेत्र की अहम भूमिका है। इस काम को पूरा करने के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ने नेशनल एक्शन प्लॉन ऑन डेयरी डेवलपमेंट तैयार किया है। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने नेशनल एक्शन प्लॉन के आधार पर बने विजन 2022 दस्तावेज को भी जारी किया। विजन डाक्यूमेंट में डेयरी के विकास की रूपरेखा बनायी गयी है और किसानों की आय दोगुनी करने के उपाय भी सुझाए गये है। विजन डाक्यूमेंट में दूध और दूध के उत्पाद को शुद्ध और सुरक्षित बनाने की भी बात कही गयी है। ■

इजराइल के प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक भारत यात्रा

भारत-इजराइल के बीच साइबर सहयोग समेत 9 अहम समझौते

इस्राइली प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू की 14 से 19 जनवरी, 2018 की भारत यात्रा, भारत-इजराइल संबंध की अभूतपूर्व पच्चीसवीं वर्षगांठ और निरंतर बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है। भारत गणराज्य तथा इजराइल राष्ट्र के बीच शिखर-सम्मेलन स्तरीय बैठकों के दौर ने, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की इजराइल की 4 से 6 जुलाई, 2017 तक की गई ऐतिहासिक यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था, दोनों देशों की सरकारों तथा लोगों के बीच संबंधों को और भी सुदृढ़ बनाया तथा इनकी रणनीतिक भागीदारी के लिए एक मजबूत आधार का निर्माण किया।

इस्राइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू 6 दिन की ऐतिहासिक यात्रा पर 14 जनवरी को भारत पहुंचे। उनके साथ 130 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी आया। गौरतलब है कि किसी विदेशी दौरे पर प्रधानमंत्री के साथ जाने वाला यह सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इस्राइली प्रधानमंत्री के प्लेन से उतरते ही श्री मोदी ने श्री नेतन्याहू से हाथ मिलाया और गले मिले। उल्लेखनीय है कि 15 साल बाद कोई इस्राइली प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आया।

यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली समकक्ष श्री बेंजामिन नेतन्याहू तीन मूर्ति मेमोरियल पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दरअसल, दोनों देशों के संबंधों को एक नई मजूबती देने के लिए दिल्ली के तीन मूर्ति स्मारक में इजरायल के ऐतिहासिक शहर हाइफा का नाम जोड़ दिया। अब इस चौक का नाम 'तीन मूर्ति हाइफा' हो गया है। हाइफा इस्राइल के एक शहर का नाम है। तीन मूर्ति पर मौजूद तीन कांस्य मूर्तियां हैदराबाद, जोधपुर और मैसूर लांसर्स का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो 15 इम्पीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड का हिस्सा थीं। इस ब्रिगेड ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 23 सितंबर 1918 को हाइफा पर विजयी हमला किया था। इसे विजयी हमले में मुस्लिम तुर्कों से फिलिस्तीनी लोगों की मुक्ति के लिए भारत के तीन राज्य (जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर) से इजरायल में सैनिक भेजे गए थे।

दोनों देशों के बीच नौ अहम समझौते

यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 15 जनवरी को साइबर सहयोग समेत 9 अहम समझौते हुए। भारत और इसराइल ने साइबर सुरक्षा, तेल और प्राकृतिक गैस, एयर ट्रांसपोर्ट, फ़िल्म प्रोडक्शन, स्वास्थ्य क्षेत्र में होम्योपैथी के लिए सहयोग के साथ ही अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने और आईओसीएल कॉप इन मेटल एयर बैटरी के साथ ही नवीनीकरण ऊर्जा सोलर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के

लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

इजराइल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान 15 जनवरी को भारत-इजराइल संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। दरअसल, दोनों प्रधानमंत्रियों ने तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में भारत और इजराइल के बीच सहयोग प्रारंभ होने का स्वागत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपस्ट्रीम क्षेत्रों तथा तेल और गैस में भावी प्रौद्योगिकियों और स्टार्ट-अपों के लिए सहयोग भी शामिल है।

उन्होंने स्थिर ऊर्जा भण्डारण प्रणालियों के लिए मेटल एयर बैट्रियों तथा सौर तापीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में सहयोग प्रारंभ करने के लिए भारतीय सरकारी क्षेत्र की कंपनियों और इजराइयली कंपनियों के मध्य सहमति को भी नोट किया तथा पक्षों के उद्योगों से आग्रह किया कि वे नवीन ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में व्यापारिक सहयोग की संभावनाओं को तलाशें। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में संधारणीय विकास हेतु नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि स्थापित करने के प्रयोजनार्थ भारत द्वारा की गई पहल का स्वागत करते हुए इजराइल ने इसका भागीदार देश बनने की अपनी इच्छा की घोषणा की।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि के माध्यम से सौर प्रौद्योगिकियों के वृहद् प्रयोग को संवर्धित करने के लिए अनुसंधान संस्थाओं और उद्योग में सहयोग का आग्रह किया, जिसमें तीसरे देशों में भी ऐसा ही सहयोग किया जाना शामिल है।

दोनों देशों के बीच सहयोग को लेकर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू का भारत दौरा बेहद अहम है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों का आपसी संबंध नीतिगत मामलों पर बढ़ती सहमति ही है।

भारत–इजराइल के बीच हुए प्रमुख समझौते

- भारत एवं इजराइल के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग
- तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के बीच एमओयू
- हवाई परिवहन समझौते में संशोधनों पर भारत और इजराइल के बीच प्रोटोकॉल
- भारत एवं इजराइल के बीच फिल्म-सह-उत्पादन पर समझौता
- होम्योपैथिक औषधियों से जुड़े अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए आयुष मंत्रालय की केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद और एकीकृत पूरक चिकित्सा केंद्र, शारे जेडेक मेडिकल सेंटर के बीच एमओयू
- अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) और टेक्नियन-इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच एमओयू
- इन्वेस्टे इंडिया और इन्वेस्टे इन इजराइल के बीच आशय ज्ञापन
- मेटल-एयर बैटरियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए आईओसीएल और फिनर्जी लिमिटेड के बीच आशय पत्र

'मेक इन इंडिया' पर जोर

दोनों प्रधानमंत्रियों ने 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए इजराइली कंपनियों की इच्छा को नोट किया। उन्होंने संयुक्त उद्यमों और संयुक्त विनिर्माण के लिए अधिक व्यापार मॉडल और भागीदारियां विकसित करने के लिए दिशा निर्धारित करना महत्वपूर्ण समझा, जिसमें रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का अंतरण तथा संयुक्त अनुसंधान और विकास भी शामिल हैं। उन्होंने रक्षा मंत्रालय से आह्वान किया कि वे सरकारी और निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी के साथ 2018 में चर्चाएं आयोजित करें, ताकि रक्षा उद्योग में व्यवहार्य, संधारणीय और दीर्घकालिक सहयोग के लिए आधार का निर्माण किया जा सके।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस वक्तव्य में कहा कि सुरक्षा के मामले में मैंने इजराइली कंपनियों को उदारीकृत एफडीआई व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि वे हमारी कंपनियों के साथ मिलकर भारत में अधिक निर्माण कर सकें।

श्री मोदी ने कहा कि हम तेल एवं गैस, साइबर सुरक्षा, फिल्म तथा स्टार्ट-अप जैसे कम तलाशे गए क्षेत्रों में सहयोग करने का साहस कर

रहे हैं। अभी-अभी किए गए समझौतों में यह परिलक्षित है। इनमें बहुत से क्षेत्र विविधिकरण तथा व्यापक संलिप्तता की हमारी इच्छा के संकेतक हैं। उन्होंने कहा कि सुदृढ साझेदारी के लिए द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना हमारे विजन का एक मुख्य अंग है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और मैं इस दिशा में और अधिक करने की जरूरत पर सहमत हैं।

कारोबार सुगमता के लिए श्री नेतन्याहू द्वारा मोदी सरकार की तारीफ

इस्राइली प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भू-राजनीतक सम्मेलन 'रायसीना संवाद' के तीसरे संस्करण का 16 जनवरी को उद्घाटन किया और इस बात पर जोर दिया कि एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरने के लिए आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक ताकत विकसित करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज भी इस उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। श्री नेतन्याहू ने भारत में लाल फीताशाही पर अंकुश लगाने और कारोबार सुगमता के लिए उठाए कदमों

को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की।

उन्होंने कहा कि एक सरकार आर्थिक प्रगति को सुगम बनाना और बाधित करना दोनों काम कर सकती है। अगर कारोबारी इकाइयों के जरिए नवोन्मेष में मददगार मुक्त बाजार उपलब्ध है तो प्रगति संभव है।

श्री नेतन्याहू ने कहा कि कमजोर नहीं टिकते, मजबूत टिकते हैं... आप मजबूत के साथ गठजोड़ करिए। इस्राइली प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए एक मजबूत सेना की जरूरत होती है और इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। यह पैसा मजबूत अर्थव्यवस्था से आता है। नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक देशों के बीच गठजोड़ होना चाहिए।

आई क्रिएट सुविधा राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और इस्राइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 17 जनवरी को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में आई क्रिएट सुविधा राष्ट्र को समर्पित की। गौरतलब है कि आई क्रिएट एक स्वतंत्र केंद्र है, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, जल, संपर्क, साइबर सुरक्षा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, बायो मेडिकल उपकरण तथा यंत्रों जैसे प्रमुख मुद्दों से निपटने के लिए सृजनात्मकता, नवोन्मेष, इंजीनियरिंग, उत्पाद डिजाइन और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के जरिए उद्यमिता को बढ़ावा देना है। आई क्रिएट का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उद्यम सृजित करने के लिए भारत में एक पारिस्थितिकी प्रणाली विकसित करना है।

एकत्र जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नये अविष्कारों की भारत और इस्राइल के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि समूचे विश्व में इस्राइल के प्रौद्योगिकी कौशल और सृजनात्मकता की ख्याति है। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं में ऊर्जा और उत्साह है। युवाओं को केवल थोड़े से प्रोत्साहन और संस्थागत सहायता की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि सरकार समूची प्रणाली को नवोन्मेष अनुकूल बनाने के लिए कार्य कर रही है, ताकि इस प्रयोजन से नई योजनाएं सामने आएं, नई योजनाओं से आविष्कार होते हैं और नये आविष्कारों से नये भारत का निर्माण करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस सफलता की पहली पूर्व शर्त साहस है। उन्होंने आई क्रिएट में नवोन्मेष कार्यों में लगे साहसी युवाओं को बधाई दी।

कालिदास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने परिपाटी और नवोन्मेष के बीच कश्मकश का जिक्र किया। उन्होंने भारत के युवाओं से आग्रह किया कि वे राष्ट्र के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए नये आविष्कार करें और कम से कम लागत पर आम आदमी के जीवन में सुधार करें। श्री मोदी ने भारत और इस्राइल के बीच खाद्य, जल, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नये आविष्कारों की दिशा में सहयोग की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 21वीं शताब्दी में मानवता के इतिहास में दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया अध्याय लिखा जाएगा।

वडराड स्थित सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र का दौरा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने 17 जनवरी को गुजरात के साबरकंथा जिले में वडराड स्थित सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र का दौरा किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेन्यामिन नेतन्याहू को इस केन्द्र की विभिन्न उपलब्धियों से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने वीडियो लिंक के जरिए कच्छ जिले के कुकामा स्थित खजूर उत्कृष्टता केन्द्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कच्छ जिले के किसानों के साथ संवाद किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इजराइल ने पूरी दुनिया को वह मार्ग दिखाया है कि आखिरकार कृषि क्षेत्र की प्रधानता वाले किसी देश में आमूलचूल बदलाव कैसे लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह बात भी रेखांकित की कि भारत वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में किस तरह से अभिनव कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंचाई के साथ-साथ खेती-बाड़ी के अभिनव तौर-तरीकों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। ■

भारत जल्द ही दुनिया का सिरमौर बनकर रहेगा

अनिल बलूनी

न्यू इंडिया के संकल्प को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस शिद्दत और विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उससे लगता है भारत जल्द ही दुनिया का सिरमौर बनकर रहेगा। जनकल्याणकारी योजनाओं और सशक्त विदेश नीति के जरिए पीएम मोदी ने जो यश और कीर्ति अब तक तक हासिल की है, नए साल में उसका सिलसिला जारी है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व पर मुहर लगाई है गैलप इंटरनेशनल ने। दरअसल गैलप इंटरनेशनल ने 50 देशों में लोगों से पूछे गए विभिन्न सवालों के आधार पर अपने वार्षिक सर्वेक्षण में पीएम मोदी को विश्व के टॉप नेताओं के तीसरे नंबर पर रखा है। अब तक यह मुकाम किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को हासिल नहीं हुआ है। इस सर्वे में पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, चीन के प्रेजिडेंट शी चिनफिंग, ब्रिटेन की पीएम टेरीजा मे जैसे दिग्गज नेताओं के ऊपर स्थान मिला है। इस सर्वे से एक बात फिर साबित हुई है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी उतनी ही प्रचंड है, जितनी देश के भीतर।

यह पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी की नीतियों, उनके व्यक्तित्व और कुशल नेतृत्व का लोहा वैश्विक संस्थानों ने माना है। इससे पहले पिछले साल वर्ल्ड बैंक ने भी मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं पर अपनी मुहर लगाई थी। इसके बाद अमेरिकी एजेंसी प्यू रिसर्च के सर्वे में भी मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर भरोसा दिखाते हुए पीएम मोदी को भारतीयों की पहली पसंद के तौर पर रखा था। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर एक अन्य वैश्विक एजेंसी मूडीज ने अपनी मुहर लगाते हुए भारत की रेटिंग को बीएए3 से बढ़ाकर बीएए2 कर दिया था।

इन तमाम उपलब्धियों से न सिर्फ मोदी जी के कुशल नेतृत्व का लोहा माना गया है, बल्कि भारत का विश्व भर में मान सम्मान भी बढ़ा है। इसलिए ये कहना सही होगा कि ये तमाम सम्मान सवा सौ करोड़ भारतीयों की उम्मीदों और विश्वास का सम्मान भी हैं।

पीएम मोदी भी सवा सौ करोड़ हिंदुस्तानियों के विश्वास, मान सम्मान और कल्याण को अपना संकल्प मानकर निरंतर भारत को प्रगति पथ पर आगे ले जा रहे हैं। इन सकारात्मक उपलब्धियों के पीछे मोदी सरकार की अथक मेहनत और दूरदर्शी आर्थिक नीतियों की बड़ी भूमिका रही है। जीएसटी और नोटबंदी जैसा साहसिक फैसला लेना किसी साधारण नेतृत्व के बस की बात नहीं, लेकिन मोदी जी ने बिना राजनीतिक नफे-नुकसान के ऐसे फैसले लिए जिससे भारत के आर्थिक परिदृश्य में क्रांतिकारी कदम माना गया है। इन फैसलों को जिस तरह देश के नागरिकों ने खुलकर समर्थन दिया उसी तरह विदेशी एजेंसियां भी इसके महत्व को पहचानने लगी हैं। इन नीतियों से भारत में बिजनेस करना आसान होगा, निवेश के निए मौके मिलेंगे, भारत उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकेगा और इससे लाखों रोजगार पैदा हो सकेंगे।

दूसरी तरफ देश के नागरिकों के लिए मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने विश्वास का जो वातावरण पैदा किया है उसकी नींव तक को हिला पाना किसी के वश की बात फिलहाल तो नहीं। जन धन योजना, स्वच्छ भारत, मुद्रा लोन योजना, उज्जवला योजना ऐसे फैसले हैं, जिनसे लोगों की आर्थिकी के साथ सामाजिक स्तर में भी बड़ा बदलाव आया है।

मोदी सरकार की विदेश नीति का लोहा दुनिया भर में माना जा रहा है। आतंक का आका पाकिस्तान आज वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ा है, अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर नकेल कसी है। इसके पीछे मोदी जी की दूरदर्शी सोच और कूटनीति का साफ प्रभाव है। यूएन में फिलिस्तीन के पक्ष में वोट करने के बाद भी इजरायल आज भारत के करीबी मित्रों में बना हुआ है। इजरायली पीएम भी ताल टोककर ये बात कहते हैं कि भारत के एक वोट से इजरायल और भारत के दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यह मोदी जी के करिश्माई व्यक्तित्व और आदर्श विदेश नीति का परिणाम है। डोकलाम में चीन से भिड़ने और चीन को वापस धकेलने से यह बात भी साबित होती है कि पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए भारत किसी भी खतरे से खेल सकता है और इस तरह के साहसिक फैसले भी सिर्फ मोदी जी जैसे विरले लोग ही ले सकते हैं।

आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर भी मोदी सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय दिया है जिससे दुनिया की तमाम ताकतें आज भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही हैं।

ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारतीयों के लिए, बल्कि संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए एक आइकन की तरह हैं और यही वजह है कि वैश्विक एजेंसियां नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और उनके करिश्माई व्यक्तित्व के आगे सजदा कर रही हैं। ■

(लेखक भाजपा, मीडिया विभाग के प्रमुख हैं)

वामपंथी दुनिया में भारत को कलंकित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं

बलबीर पुंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जबसे केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी है तबसे कुछ विपक्षी दलों द्वारा समय-समय पर कुछ बेजा नारे उछाले जा रहे हैं। मसलन देश में असहिष्णुता बढ़ गई है, संविधान खतरे में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा मंडरा रहा है, मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा है, मुस्लिम और दलित अत्याचार के शिकार हो रहे हैं- जैसे जुमलों का निरंतर योग हो रहा है। ऐसे आरोप लगाने वाले आखिर देश में किस आदर्श समाज की कल्पना करते हैं? इसका खुलासा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा की केरल इकाई के सचिव और पोलित ब्यूरो सदस्य बालाकृष्णन कोडियारी के हालिया वक्तव्यों और कुछ अन्य घटनाओं से हो जाता है। केरल में माकपा अलपुझा जिला समिति की बैठक में कोडियारी ने कहा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने चीन पर चौतरफा प्रहार के लिए गुट बनाया है। यही नहीं, उन्होंने क्रूर तानाशाह किम जोंग-उन द्वारा शासित साम्यवादी देश उत्तर कोरिया का समर्थन भी किया। कोडियारी से पहले कोड़िकोड में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन भी उत्तर कोरिया की प्रशंसा करते हुए उसे चीन से बेहतर बता चुके हैं। दिसंबर में माकपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा किम जोंग-उन की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाने का मामला भी सामने आया था।

वामपंथियों का चीन और उत्तर कोरिया के प्रति निष्ठा का बड़ा कारण वह समान वैचारिक चिंतन है जिसकी अवधारणा में अधिनायकवाद, मानवाधिकारों का हनन और विरोधियों की निर्मम हत्या निहित है। समरूपी विचारधारा के कारण ही 1962 में चीन से युद्ध के दौरान देश के वामपंथी चीन के समर्थन में थे। वर्ष 2017 में जब डोकलाम में भारत और चीन की सेना आमने-सामने थी तब भी वामपंथी खेमा चीनी हित को अधिक प्राथमिकता देता दिख रहा था।

चीन से युद्ध के दौरान देश के वामपंथी चीन के समर्थन में थे

वामपंथियों का चीन और उत्तर कोरिया के प्रति निष्ठा का बड़ा कारण वह समान वैचारिक चिंतन है जिसकी अवधारणा में अधिनायकवाद, मानवाधिकारों का हनन और विरोधियों की निर्मम हत्या निहित है। समरूपी विचारधारा के कारण ही 1962 में चीन से युद्ध के दौरान देश के वामपंथी चीन के समर्थन में थे। वर्ष 2017 में जब डोकलाम में भारत और चीन की सेना आमने-सामने थी तब भी वामपंथी खेमा चीनी हित को अधिक प्राथमिकता देता दिख रहा था।

साम्यवादी देशों के लिए राष्ट्रहितों की अनदेखी

भारतीय मार्क्सवादी जिन साम्यवादी देशों के लिए राष्ट्रहितों की अनदेखी करते हैं, आखिर उनकी वास्तविकता क्या है? साम्राज्यवादी चीन में एक ऐसी विकृत व्यवस्था है, जहां की राजनीति में हिंसक मार्क्सवादी अधिनायकवाद का प्रभुत्व है तो उसकी अर्थव्यवस्था पूंजीवाद के मकड़जाल में फंसी है। इसी खतरनाक कॉकटेल के कारण ही उसने अपनी आर्थिक समृद्धि, महानगरों में गगनचुंबी इमारतें, आधुनिक अस्त्र-शस्त्र से लैस विशाल सेना आदि का तानाबाना बुना है। चीन की चकाचौंध भी किसी छलावे से कम नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में प्रतिदिन 750 से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं, जिनमें शासन द्वारा उत्पीड़ित वर्ग की बड़ी संख्या है।

चीन में मानवाधिकार रसातल में हैं

चीन में मानवाधिकार रसातल में हैं और मौजूदा राष्ट्रपति शी चिनफिंग के शासन में तो उनकी और बुरी गत हुई है। हाल में चीनी वकील जियांग तियानयोंग को दो वर्ष कैद की सजा इसलिए दे दी गई, क्योंकि उन्होंने सरकार विरोधियों का मुकदमा लड़ने की चेष्टा की थी। चीन

की मार्क्सवादी सरकार मानवाधिकार रक्षकों, शिक्षकों और स्वतंत्र लेखकों को भी निरंतर प्रताड़ित कर रही है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी के अनुसार, 2016 में दुनिया में मृत्युदंड के 1,032 मामले सामने आए जिनमें चीन के आंकड़े शामिल नहीं हैं, क्योंकि चीन की सरकार इसे गुप्त रखती है। एमनेस्टी के अनुसार मृत्युदंड के मामले में चीन-ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इराक, सोमालिया और मिस्न जैसे इस्लामी देशों से भी काफी आगे है। दुई हुआ नामक मानवाधिकार समूह के अनुसार, वर्ष 2016 में चीन में लगभग 2,000 लोगों को फांसी दी गई थी।

चीन में धार्मिक स्वतंत्रता का गला घोंटा जा रहा है

चीन में धार्मिक स्वतंत्रता का भी गला घोंटा जा रहा है। जहां तिब्बत में सांस्कृतिक और भाषाई विरासत का दमनचक्र पहले से ही अपने चरम पर है, वहीं शिनजियांगांत में उइगर मुस्लिमों को कुरान पढ़ने, रोजा रखने, दाढ़ी बढ़ाने और बुर्का पहनने आदि पर सरकारी निषेध है। अवैध निर्माण के नाम पर कई मस्जिदों को भी ढहा दिया गया है। हाल में चीन ने मजहबी कट्टरता पर अंकुश लगाने हेतु गंसांत के मुस्लिम बहुल लिंक्सिया काउंटी में स्कूली बच्चों के किसी भी तरह के मजहबी कार्यक्रम में भाग लेने पर रोक लगा दी। इससे पहले वेनझाउ के दक्षिण-पूर्व शहर में एक स्कूल को सरकार ने इसलिए बंद कर दिया था, क्योंकि उसमें ईसाई बच्चों की जनसंख्या अधिक हो गई थी। यही नहीं, उत्तरी चीन के शांक्सीत में एक चर्च को भी सरकारी आदेश पर जमींदोज कर दिया गया था। मई 2014 के बाद से भारत में अब तक सामने आए कुछ अपवादों को असहिष्णुता और मानवाधिकारों पर आघात की संज्ञा देकर वामपंथी दुनिया में भारत को कलंकित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। चीनी सरकार द्वारा उपरोक्त प्रतिबंध और अत्याचारों पर भारतीय वामपंथियों की चुप्पी का अर्थ क्या है?

उत्तर कोरिया दमनकारी और अधिनायकवादी देश है

साम्यवादी और परमाणु संपन्न उत्तर कोरिया विश्व के सबसे दमनकारी और अधिनायकवादी देशों में से एक है जहां किम परिवार का बीते सात दशकों से शासन है। पूर्ववर्तियों की भांति तानाशाह किम जोंग-उन के दौर में भी राजनीतिक दमन, यौन हिंसा, सार्वजनिक मृत्युदंड, श्रम उत्पीड़न, यात्र पर प्रतिबंध और मजहबी संपर्क पर निषेध-शासन व्यवस्था के मुख अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2014 में एक वर्ष की पड़ताल के बाद उत्तर कोरिया में वामपंथियों की बर्बरता को विश्व के समक्ष रखा। रिपोर्ट तैयार करते समय जांच समिति को ऐसी कई महिलाएं मिली, जिन्हें अपने बच्चों को मौत के घाट उतारने के लिए विवश किया गया था। 1975-1979 के कंबोडियाई नरसंहार के बाद कोई संदेह नहीं रह जाता कि वामपंथियों के लिए मानव-जीवन और उसके सभी मूल अधिकार गौण हैं। इस कालखंड में पोल पोट की क्रांति ने लाखों राजनीतिक और वैचारिक विरोधियों को मार दिया था। लेनिनवाद, स्टालिनवाद और माओवाद सेरित इस खूनी क्रांति में सामूहिक फांसी, निर्मम हत्या, श्रम यातना सहित कुपोषण और भयंकर बीमारियों के कारण 25 तिशत कंबोडियाई आबादी (20-30 लाख) समाप्त हो गई थी। वर्ष 2009 तक लगभग 24 हजार सामूहिक कब्रें भी मिल चुकी थीं।

वर्गभेद मिटाने के लिए वामपंथी जिस मार्क्सवादी सांस्कृतिक क्रांति का यशगान करते हैं, वह वास्तव में वैचारिक विरोधियों के लहू से सिंचित है। केरल में आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ताओं की निरंतर होती निर्मम हत्या-इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इतिहास साक्षी है कि विश्व के जिस भूभाग में मार्क्सवादी व्यवस्था स्थापित हुई, वहां हिंसा को ही वैचारिक पोषण का माध्यम बनाया गया।

मार्क्सवादी सांस्कृतिक क्रांति लहू से सिंचित है

वर्गभेद मिटाने के लिए वामपंथी जिस मार्क्सवादी सांस्कृतिक क्रांति का यशगान करते हैं, वह वास्तव में वैचारिक विरोधियों के लहू से सिंचित है। केरल में आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ताओं की निरंतर होती निर्मम हत्या-इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इतिहास साक्षी है कि विश्व के जिस भूभाग में मार्क्सवादी व्यवस्था स्थापित हुई, वहां हिंसा को ही वैचारिक पोषण का माध्यम बनाया गया। इस रुग्ण प्रदर्शन में एक नेता और एक ही विचार पर विश्वास रखने का सिद्धांत है। जो असहमत हैं, उन्हें मत रखने की स्वतंत्रता तो दूर सर्वहारा हित के नाम पर जीने के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है। भारतीय वामपंथियों की विशेषता है कि सत्ता से बाहर वे लोक-अधिकारों, अभिव्यक्ति, प्रजातंत्र और संविधान की बात करते है, किंतु सत्ता में आने के बाद उन्ही मूल्यों की अविलंब हत्या कर देते है। वर्ष 1975 में आपातकाल का आरंभिक समर्थन और पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों (1977-2011) के वामपंथी शासनकाल में राजनीतिक विरोधियों का दमन और मानवाधिकारों को कुचलना इसका प्रमाण है। ■

(दैनिक जागरण से साभार)

[लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं स्तंभकार हैं]

वेल्थ के साथ वेल्नस चाहते हैं, तो भारत में अद्वितीय अवसर है: नरेन्द्र मोदी

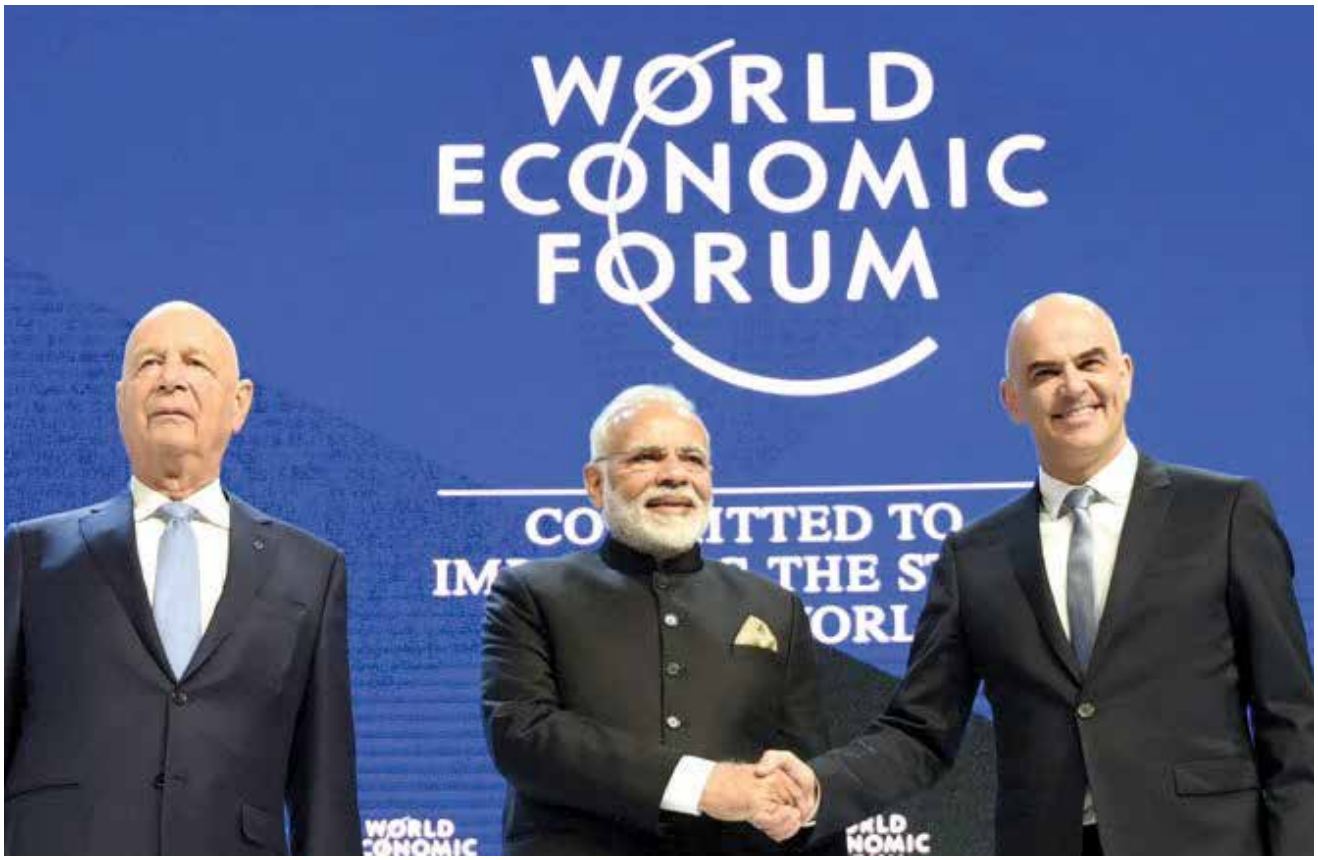

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 23 जनवरी को दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम के मंच पर संबोधन ऐतिहासिक और भारतवासियों के लिये गर्व का विषय है। इस प्रभावी संबोधन में उन्होंने भारत की शक्ति, क्षमता और उसके बहु-आयामी प्रभाव को विश्वपटल पर रेखांकित किया। दरअसल, प्रधानमंत्री का संबोधन भारत के बढ़ते कदमों और भारत के प्रति विश्व के बदलते नजरिये का परिचायक है।

प्रधानमंत्री ने विश्व का आह्वान करते हुए कहा कि अगर आप वेल्थ के साथ वेल्नस चाहते हैं और हेल्थ के साथ जीवन की समग्रता चाहते हैं, तो भारत में आपके लिए अद्वितीय अवसर उपलब्ध है। यदि आप समृद्धि के साथ शांति चाहते हैं, तो भारत में आपका अभिनंदन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विज्ञान, तकनीक और आर्थिक प्रगति के नये आयामों में एक ओर तो मानव को समृद्धि के नये रास्ते दिखाने की क्षमता है। वहीं दूसरी ओर, इन परिवर्तनों से ऐसी दरारें भी पैदा हुई हैं, जो दर्द भरी चोट पहुंचा सकती हैं। बहुत से बदलाव ऐसी दीवारें खड़ी कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी मानवता के लिए शान्ति और समृद्धि के रास्ते को दुर्गम ही नहीं दुःसाध्य बना दिया है।

श्री मोदी ने कहा कि ये दरारें, ये विभाजन और ये बाधाएं विकास के अभाव की हैं, गरीबी की हैं, बेरोजगारी की हैं, अवसरों के अभाव, और प्राकृतिक तथा तकनीकी संसाधनों पर आधिपत्य की हैं। इस परिवेश में हमारे सामने कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो मानवता के भविष्य और भावी पीढ़ियों की विरासत के लिए समुचित जवाब मांगते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या हमारी विश्व-व्यवस्था इन दरारों और दूरियों को बढ़ावा दे रही है? वे कौन सी शक्तियां हैं जो सामंजस्य के ऊपर अलगाव को तरजीह देती हैं, जो सहयोग के ऊपर संघर्ष को हावी करती हैं? और हमारे पास वे कौन से साधन हैं, वे कौन से रास्ते हैं जिनके ज़रिये हम इन दरारों और दूरियों को मिटाकर एक सुहाने

और साझा भविष्य के सपने को साकार कर सकते हैं?

उन्होंने कहा कि भारत, भारतीयता ओर भारतीय विरासत का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे लिए इस फोरम का विषय जितना समकालीन है उतना ही समयातीत भी है। समयातीत इसलिए क्योंकि भारत में अनादिकाल से हम मानव मात्र को जोड़ने में विश्वास करते आये हैं, उसे तोड़ने में नहीं, उसे बांटने में नहीं।

प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में भारत की महान संस्कृति, मान्यताओं और दर्शन को उद्धृत किया और चोटी की आर्थिक और उद्योग जगत की हस्तियों से आह्वान किया कि भारत संयोजन, सौहार्द और समन्वय की धरती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हज़ारों साल पहले संस्कृत भाषा में लिखे गये ग्रंथों में भारतीय चिंतकों ने कहाः "वसुधैव कुटुम्बकम्''। यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। तत्वतः हम सब एक परिवार की तरह बंधे हुए हैं, हमारी नियतियां एक साझा सूत्र से हमें जोड़ती हैं। वसुधैव कुटुम्बकम् की यह धारणा निश्चित तौर पर आज दरारों और दूरियों को मिटाने के लिए और भी ज्यादा सार्थक है।

श्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज सम्पूर्ण विश्व के लिये एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत ने इस चुनौती से निपटने के लिये न केवल लक्ष्य निर्धारित किये, बल्कि इस दिशा में लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई अभूतपूर्व कदम भी उठाये। यह पहल भी भारत ने अपने दर्शन "भूमि माता, पुत्रो अहम् पृथ्व्याः" के आधार पर धरती को माता मानकर इस विषय पर संवेदनशील रुख अपनाया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हज़ारों साल पहले भारत में लिखे गए सबसे प्रमुख उपनिषद 'इशोपनिषद' की शुरुआत में ही तत्त्व द्रष्टा गुरु ने अपने शिष्यों से परिवर्तनशील जगत के बारे में कहाः

'तेन त्यक्तेन भुन्जीथा, मागृधःकस्यस्विद्धनम्।

यानी संसार में रहते हुए उसका त्याग पूर्वक भोग करो, और किसी दूसरे की सम्पत्ति का लालच मत करो। ढाई हज़ार साल पहले भगवान् बुद्ध ने अपरिग्रह यानि आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल को अपने सिद्धांतों में प्रमुख स्थान दिया।

उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण में व्याप्त भयंकर कुपरिणामों के इलाज का एक अचूक नुस्खा है – प्राचीन भारतीय दर्शन का मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य। यही नहीं, इस दर्शन से जन्मी योग और आयुर्वेद जैसी भारतीय परम्पराओं की समग्र पद्धति न सिर्फ परिवेश और हमारे बीच के दरारों को पाट सकती है, बल्कि हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य और संतुलन भी प्रदान करती है।

श्री मोदी ने कहा कि वातावरण को बचाने और जलवायु परिवर्तन का प्रतिकार करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान, एक बहुत बड़ा लक्ष्य मेरी सरकार ने देश के सामने रखा है। सन् 2022 तक हमें भारत में 175 GW रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करना है। पिछले करीब तीन वर्षों में 60 GW, यानी इस लक्ष्य का एक तिहाई से भी अधिक हम प्राप्त कर चुके हैं।

हज़ारों साल पहले संस्कृत भाषा में लिखे गये ग्रंथों में भारतीय चिंतकों ने कहाः "वसुधैव कुटुम्बकम्"। यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। तत्वतः हम सब एक परिवार की तरह बंधे हुए हैं, हमारी नियतियां एक साझा सूत्र से हमें जोड़ती हैं। वसुधैव कुटुम्बकम् की यह धारणा निश्चित तौर पर आज दरारों और दूरियों को मिटाने के लिए और भी ज्यादा सार्थक है।

प्रधानमंत्री जी ने हर वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम के मंच पर भी दोहराया। उन्होंने आतंकवाद के व्यापक खतरे को स्पष्ट रूप से पराजित करने के लिये समग्र विश्व से एकजुट होने की अपील की 'गुड टेररिज्म' और 'बैड टेररिज्म' के नजरिये को खत्म करने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री जी ने भूमंडलीकरण के खिलाफ संरक्षणवाद की नीति

पर कड़ा वार करते हुए कहा कि पूरी दुनिया को इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जिसका समाधान आपसी सहमति और एकजुट होकर करने से संभव होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत से समाज और देश ज्यादा से ज्यादा आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ग्लोबलाइजेशन अपने नाम के विपरीत सिकुड़ रहा है। इस प्रकार

बहुत से समाज और देश ज्यादा से ज्यादा आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ग्लोबलाइजेशन अपने नाम के विपरीत सिकुड़ रहा है। इस प्रकार की मनोवृत्तियों और गलत प्राथमिकताओं के दुष्परिणाम को जलवायु परिवर्तन या आतंकवाद के ख़तरे से कम नहीं आंका जा सकता। हालांकि हर कोई इंटरकनेक्टेड विश्व की बात करता है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की चमक कम हो रही है।

की मनोवृत्तियों और गलत प्राथमिकताओं के दुष्परिणाम को जलवायु परिवर्तन या आतंकवाद के ख़तरे से कम नहीं आंका जा सकता। हालांकि हर कोई इंटरकनेक्टेड विश्व की बात करता है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की चमक कम हो रही है।

श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्श अभी भी सर्वमान्य हैं। वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन भी व्यापक है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने हुए विश्व संगठनों की संरचना, व्यवस्था और उनकी कार्य पद्धति क्या आज के मानव की आकांक्षाओं और उसके सपनों को, आज की वास्तविकता को परिलक्षित करते हैं?

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लोकतंत्र देश की स्थिरता, निश्चितता और सतत विकास का मूल आधार है। धर्म, संस्कृति, भाषा, वेश-भूषा और खान-पान की अपार विविधता से भरे-पूरे भारत के लिए लोकतंत्र महज़ एक राजनैतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है, जीवन शैली है। हम भारतीय यह भली-भांति जानते और समझते हैं की विविधता की अनेकता को सौहार्द, सहयोग और संकल्प की एकता में बदलने के लिए लोकतांत्रिक परिवेश और स्वतंत्रताओं का महत्व क्या है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ हमारी विविधता का ही पालन-पोषण नहीं करता, बल्कि सवा सौ करोड़ से भी अधिक भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उनके समुचित विकास के लिए आवश्यक परिवेश, रोड मैप और खांका भी प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य और समावेशी आर्थिक विकास और प्रगति में तमाम दरारों को पाटने की संजीवनी शक्ति है। भारत के साठ करोड़ मतदाताओं ने 2014 में तीस साल बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया। हमने किसी एक वर्ग या कुछ लोगों के सीमित विकास का नहीं, बल्कि सबके विकास का संकल्प किया। मेरी सरकार का सिद्धांत हैः "सबका साथ -सबका विकास"। प्रगति के लिए हमारा विज़न समावेशी है, हमारा मिशन समावेशी है।

श्री मोदी ने कहा कि यह समावेशी दर्शन मेरी सरकार की हर नीति का हर योजना का आधार है। चाहे वह करोड़ों लोगों के लिए पहली बार बैंक खाते खुला के वित्तीय समावेशन करना हो, या गरीबों तक, हर जरूरतमंद तक डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या फिर जेंडर जस्टिस के लिए 'बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ'। ■

दिसंबर, 2017 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 3.58 प्रतिशत

मासिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर दिसंबर, 2017 के दौरान (दिसंबर, 2016 की तुलना में) 3.58 प्रतिशत (अनंतिम) रही, जबकि पिछले महीने यह 3.93 प्रतिशत (अनंतिम) थी। वहीं, पिछले वर्ष के इसी महीने में यह 2.10 प्रतिशत रही थी। वित्त वर्ष में अब तक क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति दर 2.21 प्रतिशत आंकी गई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति दर 3.71 प्रतिशत थी। विभिन्न जिंस समूहों के सूचकांक में उतार-चढ़ाव इस प्रकार रहेः

प्राथमिक वस्तुएं (भारांक 22.62 प्रतिशत)

इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 135.6 अंक (अनंतिम) से 2.9 प्रतिशत घटकर 131.7 अंक (अनंतिम) रह गया। महीने के दौरान जिन समूहों और वस्तुओं के सूचकांक में उतार-चढ़ाव देखे गए, वे इस प्रकार हैंः

'खाद्य उत्पाद' समूह का सूचकांक पिछले महीने के 150.6 अंक (अनंतिम) से 4.3 प्रतिशत घटकर 144.1 अंक (अनंतिम) रह गया। ऐसा फल एवं सब्जियों (14 %), मटर/चावली (6%), चना एवं अंडे (प्रत्येक 5 %), राजमा एवं पोल्ट्री चिकन (प्रत्येक 4%), कॉफी एवं अंतर्देशीय मछली (प्रत्येक 3%), उड़द एवं चाय (प्रत्येक 2%) और मक्का एवं मसूर (प्रत्येक 1%) के दाम घटने के कारण संभव हुआ। 'गैर-खाद्य पदार्थ' समूह का सूचकांक पिछले महीने के 116.9 अंक (अनंतिम) से 1.8 प्रतिशत बढ़कर 119.0 अंक (अनंतिम) हो गया।

'खनिज' समूह का सूचकांक पिछले महीने के 129.3 अंक (अनंतिम) से 5.4 प्रतिशत घटकर 122.3 अंक (अनंतिम) रह गया। ऐसा तांबा सांद्र (14%) और सीसा सांद्र एवं जस्ता सांद्र (प्रत्येक 7%) के दाम घटने के कारण संभव हुआ।

निर्मित उत्पाद (भारांक 64.23 प्रतिशत)

इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 113.9 अंक (अनंतिम) से 0.1 प्रतिशत बढ़कर 114.0 अंक (अनंतिम) हो गया। इस महीने के दौरान विभिन्न समूहों एवं मदों में जो परिवर्तन देखे गए इनका उल्लेख निम्न है :

'खाद्य उत्पादों के निर्माण' का सूचकांक पिछले महीने के 127.9 अंक (अनंतिम) से 0.4 प्रतिशत घटकर 127.4 अंक (अनंतिम) रह गया। ऐसा शीरा (20%), गुड़ एवं बेसन (प्रत्येक 6%), चीनी, शहद और मिल्क पाउडर (प्रत्येक 4%), कॉफी पाउडर एवं खोई (प्रत्येक 3%), प्रसंस्कृत चाय, मैदा एवं सूजी (प्रत्येक 2%) और बासमती चावल एवं इंस्टैंट कॉफी (प्रत्येक 1%) के दाम घटने के कारण संभव हुआ। 'वस्त्रों के निर्माण' समूह का सूचकांक पिछले महीने के 113.5 अंक (अनंतिम) से 0.4 प्रतिशत घटकर 113.0 अंक (अनंतिम) रह गया। ■

जीएसटी परिषद की 25वीं बैठक में कई प्रमुख नीतिगत बदलाव

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 18 जनवरी को नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। जीएसटी परिषद द्वारा अपनी 25वीं बैठक में निम्नलिखित नीतिगत बदलावों की अनुशंसा कीः

फॉर्म जीएसटीआर-1 (आपूर्ति विवरण), फॉर्म जीएसटीआर-5 (अनिवासी टैक्स योग्य व्यक्ति) अथवा फॉर्म जीएसटीआर- 5ए (ओआईडीएआर) दाखिल करने में विफल रहने पर किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा देय विलंब शुल्क को घटाकर 50 रुपये प्रतिदिन किया जा रहा है और यह कोई भी फॉर्म दाखिल न करने वालों के लिए 20 रुपये प्रतिदिन होगा। फॉर्म जीएसटीआर- 6 (इनपुट सेवा वितरक) दाखिल करने में विफल रहने पर देय विलंब शुल्क 50 रुपये प्रतिदिन होगा।

स्वैच्छिक पंजीकरण प्राप्त करने वाले कर योग्य लोगों को अब पंजीकरण की प्रभावी तिथि के बाद एक वर्ष की समाप्ति से पहले भी पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी।

जीएसटी प्रणाली अपनाने वाले करदाताओं के लिए पंजीकरण रद्द करने हेतु फॉर्म जीएसटी आरईजी-29 दाखिल करने की अंतिम तिथि तीन माह और बढ़ाकर 31 मार्च 2018 की जा रही है।

ई-वे बिल सृजित, संशोधन एवं रद्द करने की सुविधा प्रायोगिक आधार पर nic.in पोर्टल पर मुहैया कराई जा रही है। इस व्यवस्था के पूरी तरह परिचालन में आ जाने पर ई-वे बिल प्रणाली ewaybillgst.gov.in पोर्टल पर काम करना शुरू कर देगी।

ई-वे बिल से संबंधित नियमों में कुछ विशेष संशोधन किए जा रहे हैं। इन नियमों को 1 फरवरी, 2018 से वस्तुओं की अंतर-राज्य आवाजाही के लिए देश भर में अधिसूचित किया जाना है। इसी तरह एक विशेष तिथि से राज्य के भीतर वस्तुओं की आवाजाही के लिए भी इन्हें अधिसूचित किया जाना है जिसकी घोषणा प्रत्येक राज्य द्वारा अलग-अलग की जाएगी, लेकिन यह तिथि 1 जून 2018 से आगे नहीं जाएगी। दरअसल, हस्तशिल्प पर गठित समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट और सिफारिशों को भी जीएसटी परिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ■

पीएम मोदी ने भारत की विदेश नीति में आमूलचूल बदलाव कर आर्थिक रिश्तों को दी मजबूती

बैजयंत जय पांडा

इस साल गणतंत्र दिवस से पहला पखवाड़ा भारत की विदेश नीति को समर्पित रहा। राजधानी दिल्ली में 16 से 18 जनवरी के बीच तीसरे 'रायसीना डायलॉग' का आयोजन हुआ। सैकड़ों वैश्विक नीति-निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों, कैबिनेट मंत्रियों, भारतीय अधिकारियों, अकादमिक जगत की हस्तियों, निजी क्षेत्र के दिग्गजों और मीडिया के नामचीन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) और विदेश मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में होता है। इस बार इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया। अब यह भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख आयोजन बन गया है। इसके उद्घाटन सत्र का सार यही रहा कि भारत और इजरायल के बीच रिश्ते और घनिष्ठ होते जा रहे हैं। नेतन्याहू के भारतीय दौरे के बीच ही एक पड़ाव यह भी था। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की बाबत उन्होंने दोहराया कि मुकाबले में केवल मजबूत और दमदार प्रतिद्वंद्वी ही अपना अस्तित्व बचा पाता है और ऐसे में आपको मजबूत साथी के साथ ही गठजोड़ करना पड़ता है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है तब से भारतीय विदेश नीति में आमूलचूल बदलाव देखने को मिला है। इजरायल के अस्तित्व में आने के बाद वहां का दौरा करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। भारत इजरायल का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है, जहां दोनों देश अरबों डॉलर के रक्षा सौदों में लगे हैं। दोनों देशों ने परस्पर सामरिक एवं आर्थिक रिश्तों को मजबूती दी है।

जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है तब से भारतीय विदेश नीति में आमूलचूल बदलाव देखने को मिला है। इजरायल के अस्तित्व में आने के बाद वहां का दौरा करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। भारत इजरायल का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है, जहां दोनों देश अरबों डॉलर के रक्षा सौदों में लगे हैं। दोनों देशों ने परस्पर सामरिक एवं आर्थिक रिश्तों को मजबूती दी है।

अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते नए दौर में दाखिल

अमेरिका के साथ भी भारत के रिश्ते एक नए दौर में दाखिल हुए हैं। अक्टूबर, 2017 में भारतीय दौरे के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा था कि अमेरिका और भारत गहन सामरिक साझेदार के तौर पर उभरे हैं जहां रक्षा संबंधों, आतंक विरोधी अभियान के साथ-साथ ऊर्जा सहयोग में दोनों देशों के रिश्तों में और प्रगाढ़ता आई है। भारत और अमेरिका मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास, रक्षा तकनीक एवं व्यापार पहल और आसान आवाजाही एवं ढुलाई के लिए लेमोओ जैसे समझौतों के जरिये काफी करीब आ चुके हैं। उस दौरान टिलरसन ने पाकिस्तान का भी जिक्र करते हुए कहा था कि जो देश अपनी सरकारी नीति में आतंक का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मात खाने और बदनामी के अलावा कुछ और हासिल नहीं होगा।

ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी

वहीं इस साल के पहले दिन ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिये पाकिस्तान को सन्न कर दिया। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान अमेरिका को बरगलाता आया है और इस आधार पर उन्होंने पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ संघर्ष में पाकिस्तान ने सिर्फ झूठ और फरेब का सहारा लिया है। ट्रंप ने कहा कि पंद्रह वर्षों के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर की सहायता दी और उधर पाकिस्तान आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह

मुहैया कराता रहा। पाकिस्तान द्वारा अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क पर उचित कार्रवाई में हिचक से यह जाहिर भी होता है।

चीन का मानना है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान ने बहुत त्याग किया

आतंक को पोषित करने के चलते पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी भर्त्सना हो रही है। आइएसआइएस को हराने के लिए बने वैश्विक गठजोड़ का भी वह हिस्सा नहीं है। दिलचस्प बात यही है कि चीन का नजरिया अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से अलग है। बीजिंग का मानना है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान ने बहुत त्याग किया है। चीन पाकिस्तान में 52 अरब डॉलर के भारी-भरकम निवेश से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी का निर्माण कर रहा है, जिसे चीन अपनी महत्वाकांक्षी वन बेल्ट, वन रोड परियोजना का अहम हिस्सा मानता है। वहीं मसूद अजहर जैसे दुर्दांत आतंकी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिशों पर भी चीन संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर अड़ंगा डालता रहा है, जो आतंकवाद को लेकर उसके रवैये की कलई खोलता है। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती गलबहियों पर अमेरिका वक्त-बेवक्त आंखें तरेरता रहता है। जहां उसने पाकिस्तान को दी जाने वाली दो अरब डॉलर की सहायता बंद कर दी, तो दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता पर भी कड़ी नजर रखता है।

आतंक की जड़ों ने शांति की फसल को लहलहाने नहीं दिया

शुरुआत में मोदी ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सामान्य करने की कोशिश भी की। इसी कड़ी में वह 2015 में अचानक पाकिस्तान भी गए, लेकिन पाकिस्तान की व्यवस्था में गहराई तक पैठ की हुई आतंक की जड़ों ने शांति की फसल को लहलहाने नहीं दिया और मोदी के दौरे के चंद रोज बाद ही पठानकोट एयरबेस पर हमला हो गया। फिर उड़ी हमले के साथ तो अति ही हो गई जिसके जवाब में भारत ने सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। अब हम इस आतंक पसंद पड़ोसी को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है तो मुंबई में 26/11 हमले के बाद से हालात काफी सुधरे हैं। तटीय सुरक्षा प्राथमिकता सूची में आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय तटीय सीमा पुलिस बल की योजना पर काम कर रहा है। साथ ही भारत 2018 तक पाकिस्तान से लगी सीमा पर बाड़ लगाने के साथ ही वहां अत्याधुनिक सीसीटीवी, थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन डिवाइस और मॉनिटरिंग सेंसर की व्यवस्था करने जा रहा है। पूरब के साथ जुड़ने में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। भारत-आसियान संबंध अपने शिखर पर हैं और यह हमारी विदेश नीति का अभिन्न अंग बन गए हैं। नई दिल्ली में जल्द ही भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के आयोजन से इसमें एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। साथ ही आसियान के दस राष्ट्रप्रमुख ही इस बार गणतंत्र दिवस की शोभा भी बढ़ाएंगे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है तो मुंबई में 26/11 हमले के बाद से हालात काफी सुधरे हैं। तटीय सुरक्षा प्राथमिकता सूची में आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय तटीय सीमा पुलिस बल की योजना पर काम कर रहा है। साथ ही भारत 2018 तक पाकिस्तान से लगी सीमा पर बाड़ लगाने के साथ ही वहां अत्याधुनिक सीसीटीवी, थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन डिवाइस और मॉनिटरिंग सेंसर की व्यवस्था करने जा रहा है।

बिम्सटेक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच एक सेतु की तरह है

बहुस्तरीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पर बंगाल की खाड़ी देशों की पहल यानी बिम्सटेक की भी अपनी अहमियत है। रायसीना डायलॉग में इससे जुड़े एक सत्र की मैंने अध्यक्षता भी की। बिम्सटेक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच एक सेतु की तरह है। यह दक्षेस और आसियान के साथ मिलकर क्षेत्र में आतंक विरोधी अभियान में सार्थक भूमिका निभा सकता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी बिम्सटेक को भारतीय विदेश नीति के बेहद अहम लक्ष्यों को हासिल करने का एक स्वाभाविक विकल्प बता चुकी हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कुख्यात लालफीताशाही को खत्म करते हुए 'मदद' पोर्टल के रूप में एक सराहनीय पहल भी की है। हमारा कार्यालय समय-समय पर इसके जरिये लोगों की मदद करता है। हाल में ही केंद्रपाड़ा के शशिकांत बिस्वाल को बचाने में यह मददगार रहा। बिस्वाल पश्चिम एशिया में एक कबूतरबाज एजेंट के चंगुल में फंसे हुए थे।

मोदी सरकार की कथनी और करनी पर भी सभी की नजरें लगी हैं

बीते दो हफ्तों में इस साल के लिए विदेश नीति की बुनियाद तैयार कर दी गई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में क्या होता है। चूंकि अगले आम चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं हैं, तो सरकार की कथनी और करनी पर भी सभी की नजरें लगी होंगी। भू-राजनीतिक प्रभाव में प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर उभरने के लिए भारत को अपनी सामरिक ताकत और व्यापक आर्थिक क्षमताओं का निरंतर लाभ उठाते रहना चाहिए। ■

(दैनिक जागरण से साभार)

[लेखक बीजू जनता दल के लोकसभा सदस्य हैं]

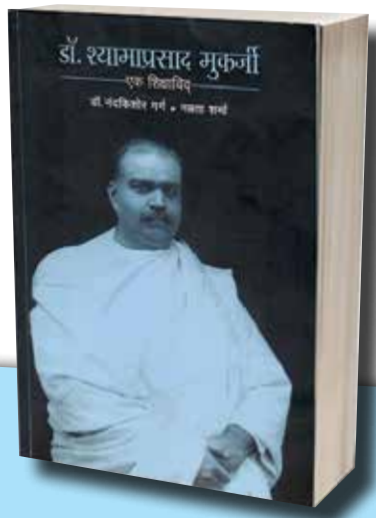

डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी : एक शिक्षाविद्

लेखक : डॉ. नंद किशोर गर्ग एवं नम्रता शर्मा
पृष्ठ : 244
मूल्य : रु. 270 (पेपरबैक)
प्रकाशक : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज-2, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी का शिक्षा चिंतन

- भारत के आधुनिक विद्यार्थियों को भारत के प्राचीन इतिहास और सभ्यता की पुनर्व्याख्या करके उसे आधुनिक आवश्यकताओं से जोड़ना चाहिए।
- मातृभाषा को शिक्षण का माध्यम बनाना चाहिए।
- शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्र, स्वायत्त एवं प्रगतिशील विचारों का अधिष्ठान बनाना, जहां सभी धर्मों, वर्णों, सम्प्रदायों, वर्गों के लोग पारस्परिक सहयोग और सद्भावना के वातावरण में शिक्षा के विकास के लिए कर्तव्यबद्ध हों।

भारत को उसके 'स्व' से साक्षात्कार कराने में जिन महापुरुषों ने महती भूमिका निभाई, उनमें डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी का नाम उल्लेखनीय है। उनका व्यक्तित्व विराट् था। वे शिक्षाविद् थे, प्रशासक थे, समाजसेवी थे और राजनेता थे। अलग-अलग भूमिकाओं में उन्होंने अपना श्रेष्ठ योगदान किया।

सामान्य तौर पर डॉ. मुकर्जी के राजनीतिक योगदान की ही चर्चा होती है और इस पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इसलिए सद्यः प्रकाशित पुस्तक 'डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी : एक शिक्षाविद्' इस दिशा में महत्त्वपूर्ण है।

पुस्तक का लेखन डॉ. नंद किशोर गर्ग और नम्रता शर्मा ने संयुक्त रूप से किया है। डॉ. गर्ग स्वयं राजनेता हैं और शिक्षा जगत से जुड़े हैं। वहीं नम्रता शर्मा सहायक प्राध्यापक हैं। लेखकद्वय ने डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी के शिक्षा चिंतन को सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत किया है। यह अकादमिक पुस्तक है, जिसके लेखन में शोध और विश्लेषण का सहारा लिया गया है तथा फुटनोट का प्रयोग किया गया है।

इस पुस्तक की रचना के पीछे की मंशा जाहिर करते हुए लेखकद्वय प्रस्तावना में लिखते हैं, "डॉ. मुकर्जी के व्यक्तित्व के राजनीतिक आयाम पर बहुत कुछ लिखा गया है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत कुछ लिखा जाना शेष है। उनका व्यक्तित्व उनके राजनीतिक जीवन से इतर भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।"

इस पुस्तक में कुल 9 अध्याय हैं – प्रस्तावना, वंश परंपरा और विरासत, प्रारंभिक जीवन, विद्यार्थी से विचारक तक, युवा कुलपति, डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी : शिक्षा के सांप्रदायीकरण से परे, उत्कृष्ट शिक्षाविद् : डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी, डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी के शैक्षणिक विचारों की प्रासंगिकता और उपहार; जिनके माध्यम से डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी के शिक्षा चिंतन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

वैसे तो इस पुस्तक में डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी के शिक्षा चिंतन के बारे में विस्तार से बताया गया है, लेकिन इसके साथ कई और मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। पुस्तक में यथास्थान डॉ. मुकर्जी के अनेक दुर्लभ चित्रों को भी प्रस्तुत किया गया है।

संप्रति केंद्र में भाजपानीत सरकार है। भाजपा भारतीय जनसंघ का परवर्ती संगठन हैं। गौरतलब है कि डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। सो, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह पुस्तक और अधिक प्रासंगिक है। राष्ट्रीय विचार के कार्यकर्ताओं के लिए यह पुस्तक बहुत लाभप्रद और प्रेरक सिद्ध होगी।

यह अकादमिक पुस्तक है, लेकिन भाषा सहज और सरल है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने इसे प्रकाशित किया है, इसलिए प्रिंटिंग का स्तर अच्छा है।

यह पुस्तक डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी के शिक्षा चिंतन को समझने की दृष्टि से एक प्रामाणिक दस्तावेज़ है। कुल मिलाकर यह पठनीय और संग्रहणीय है। शैक्षिक जगत के अध्येताओं को तो इसे अवश्य पढ़नी चाहिए। ■

समीक्षक : संजीव कुमार सिन्हा

पत्र-पत्रिकाओं से...

आसियान के मेहमान

हर साल गणतंत्र दिवस पर किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को अतिथि के तौर पर बुलाया जाता रहा है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि किसी एक देश के नहीं, बल्कि दस देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत के मेहमान हैं। ये देश हैं सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमा, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, विएतनाम, लाओस और फिलीपीन्स। इन सभी देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित करने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या मंशा रही होगी, यह बिलकुल साफ है। वे आसियान देशों के साथ भारत की व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं और इस सिलसिले में अतिथि नेताओं के साथ बुधवार तथा गुरुवार को उनकी बातचीत हुई। उम्मीद है कि अलग-अलग द्विपक्षीय वार्ताओं का दौर इन देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूती देगा। आसियान के सदस्य-देशों या दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध बढ़ाने की ललक नई नहीं है। दरअसल, भारत की विदेश नीति और विदेश व्यापार में आसियान के करीब आने की ललक उदारीकरण का दौर शुरू होने के साथ ही तेज हुई, क्योंकि निवेश और बाजार के लिए नए-नए क्षेत्रों की तलाश थी और इस क्रम में उस वक्त तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था कहे जाने वाले देशों की तरफ भारत का मुखातिब होना स्वाभाविक था।

- (जनसत्ता, १७ जनवरी, २०१८)

उपलब्धियां और सपने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में जो कुछ भी कहा, उसमें उनका आत्मविश्वास साफ नजर आया। दरअसल दुनिया की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना विश्वास प्रदर्शित कर केंद्र सरकार की आर्थिक नीति पर अपनी मुहर लगा दी है। हाल में विश्व बैंक ने कहा कि इस साल भारत सबसे तेज विकास वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उसने अपनी 'ग्लोबल इकनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट' में 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.3 प्रतिशत होने का अनुमान जाहिर किया। पिछले महीने ब्रिटेन की कंसल्टेंसी फर्म 'सेंटर फॉर इकनॉमिक ऐंड बिजनेस रिसर्च' (सीईबीआर) ने भी कहा था कि 2018 में भारत दुनिया की टॉप-5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। आईएमएफ और कुछ रेटिंग एजेंसियां भी ऐसा ही संकेत दे चुकी हैं। नोटबंदी और जीएसटी जोखिम भरा कदम था, जिस पर प्रधानमंत्री को विपक्ष द्वारा घेरा भी गया, लेकिन तमाम वित्तीय संस्थाएं मान रही हैं कि इनका असर अब खत्म हो चुका है। इससे पीएम मोदी उत्साहित हैं। उनका यह उत्साह दावोस में विश्व आर्थिक फोरम की सालाना बैठक में जरूर दिखेगा।

इसके बारे में प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा कि आज अर्थजगत का ध्यान भारत पर केंद्रित है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और पूरा विश्व इसे मान रहा है। आज दुनिया भारत की नीतियों और विकास के बारे में सीधे देश के मुखिया से सुनना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे दावोस में 125 करोड़ भारतीयों की सक्सेस स्टोरी सुनाने में गर्व महसूस होगा। हालांकि, पीएम को इस बात का थोड़ा मलाल भी है कि सरकार के काम के रूप में सिर्फ नोटबंदी और जीएसटी की ही चर्चा होती है। उनका आग्रह था कि उनकी और उपलब्धियों को भी देखा जाए। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि सरकार ने बड़ी संख्या में लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। लड़कियों के अनेक स्कूलों में शौचालय बनवाए गए हैं। करीब 3.30 करोड़ लोगों के घर गैस पहुंचाई गई। 90 पैसे में गरीब लोगों का इंश्योरेंस हुआ। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर कहा कि पिछले एक साल में संगठित क्षेत्र में 70 लाख ईपीएफ अकाउंट खुले हैं। एक साल में 10 करोड़ लोगों ने मुद्रा योजना का लाभ लिया है।

ये आंकड़े बताते हैं कि लोगों को रोजी-रोजगार मिल रहा है। किसानों की दुर्दशा को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में पीएम ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक समेत कई राज्यों में इसका फायदा हो रहा है। हमारा सपना है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाए। आगामी बजट को लेकर पीएम ने कहा कि मोदी का एक ही मंत्र है- विकास, विकास, विकास और सबका साथ-सबका विकास। इस तरह प्रधानमंत्री ने भविष्य को लेकर अपना विजन एक बार फिर साफ कर दिया है।

- (नवभारत टाइम्स, १३ जनवरी, २०१८)

स्कूट विचार...

हम जहां भी सत्ता में हैं वहां हमारे दो मार्गनिर्देशी सिद्धांत होने चाहिए कि तेजी से आर्थिक परिवर्तन लाया जाए, तेजी से समाज विकास का कार्य सम्पन्न हो। जब तक हम सब में बराबर विकास को सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक हम आशा नहीं कर सकते हैं कि हमारे लिए लोगों का समर्थन जारी रहेगा।

— कुशाभाऊ ठाकरे

पाकिस्तान के साथ तब तक कोई सार्थक बातचीत नहीं हो सकती, जब तक कि वो आतंकवाद का प्रयोग अपनी विदेशी नीति के एक साधन के रूप में करना नहीं छोड़ देता।

— अटल बिहारी वाजपेयी

प्रस्तुति: पंकज आनंद

आज ही लीजिए

कमल संदेश

की सदस्यता

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

और

दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष श्री क्लॉज़ श्वाब और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति श्री एलेन बर्सेट के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

दावोस में विभिन्न कंपनियों के सीईओ की एक गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में इजराइली प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी श्रीमती सारा नेतन्याहू का स्वागत करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

अहमदाबाद में आईक्रिएट सेंटर के उद्घाटन अवसर पर इजराइली प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

अहमदाबाद में आईक्रिएट सेंटर के उद्घाटन के बाद जनाभिवादन स्वीकार करते इजराइली प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी के कार्य का शुभारंभ करने के बाद एक विशाल रैली को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

भारत के
300 जिले
3,00,000 गाँव और
10 राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को
खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए
देशवासियों को हार्दिक बधाई

स्वच्छ भारत मिशन

2 अक्टूबर, 2014 से अब तक 5.94 करोड़ शौचालय निर्मित किए गए हैं

संकल्प से सिद्धि – 2019 तक खुले में शौच से मुक्ति की दिशा में भारत अग्रसर

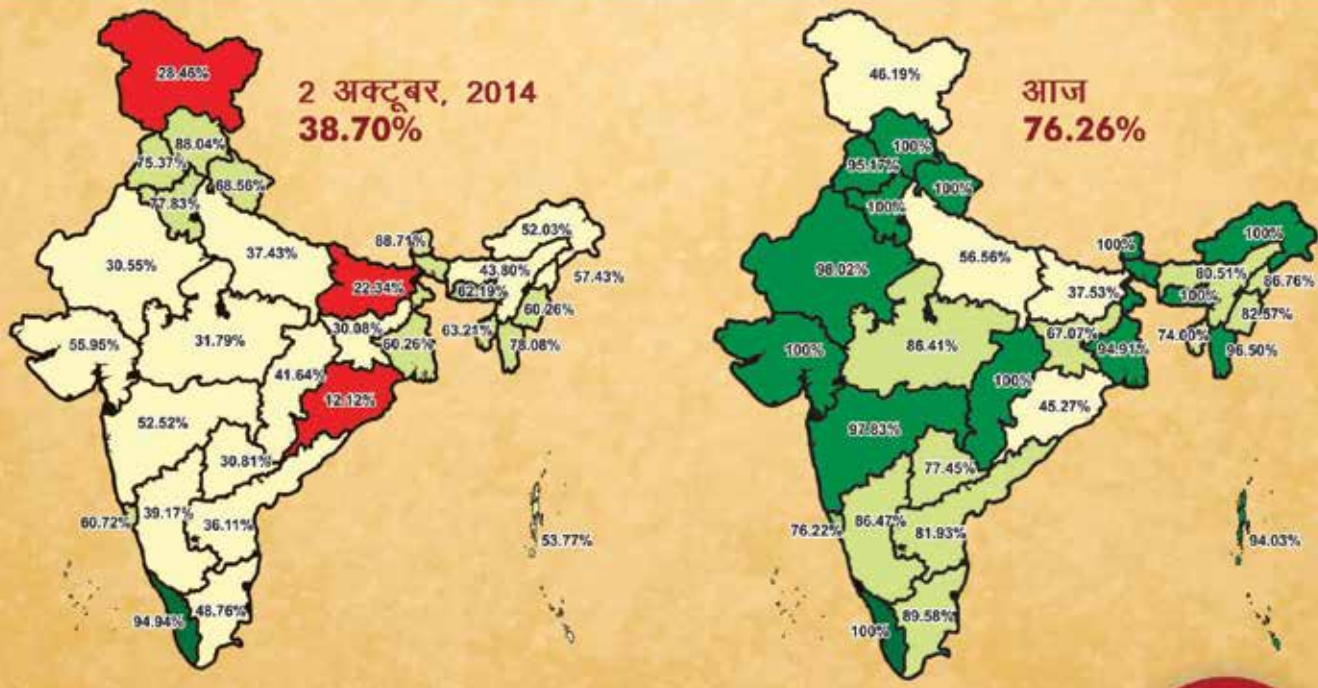

कम लागत और पर्यावरण अनुकूल
दो गड्ढों वाले शौचालय
का निर्माण करें

हम से जुड़ें @swachhbharat SBMGramin YouTube tinyurl.com/sbmgramin

विश्व के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन और शौचालय उपयोग कार्यक्रम से जुड़ें